RAJRAS

राजस्थान समसामयिकी

जनवरी से अगस्त

2020

© 2020 All Rights Reserved with RAJRAS Ventures LLP

This PDF eBook is only for personal reference. No part of this eBook (PDF) may be reproduced or transmitted by any form or by any means electronic or mechanical including printing, photocopying or recording or by any information storage and retrieval system or used in any manner without written permission from RajRAS Ventures LLP. RajRAS Ventures LLP may take legal action, file for criminal infringement & seek compensation for the loss.

Disclaimer: RajRAS Ventures LLP has obtained the information contained in this work from sources believed to be reliable. Care has been taken to publish information, as accurate as possible. RajRAS Ventures LLP nor its authors guarantee the accuracy or completeness of any information published herein, and neither RajRAS Ventures LLP nor its authors, affiliates, publishers or any other party associated with RajRAS Ventures LLP shall be liable or responsible for any errors, omissions or damages arising out of use of this information. RajRAS Ventures LLP and its authors are just making an attempt to provide information and not attempting to offer any professional services.

All disputes will be subject to Udaipur, Rajasthan Jurisdiction.

INDEX

चर्चित व्यक्ति 1

चर्चित स्थान 11

पर्यावरण 19

सरकारी परियोजनायें 27

सामान्य करंट अफेयर्स 44

सरकारी apps एवं पोर्टल 64

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 69

राजस्थान बजट 2020-21 75

चर्चित व्यक्ति

पुरस्कार

यश मिश्रा

कोटा के नौवीं कक्षा के छात्र यश मिश्रा को 22 जनवरी 2020 को नई दिल्ली में राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा बाल शक्ति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया।

गुलाब कोठारी

राजस्थान पत्रिका समूह के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को पत्रकारिता के प्रति उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर 16 नवंबर को प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राय पुरस्कार प्रदान किया गया।

हृदयेश्वर सिंह भाटी

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद द्वारा हृदयेश्वर सिंह भाटी को नवाचार श्रेणी में प्रधान मंत्री बाल पुरस्कार 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया। वे गोलाकार शतरंज बनाकर तथा उसका पेटेंट लेकर देश के सबसे छोटे पेटेंट धारक बन गए है।

रूमा देवी

राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास जन्मी, 31 वर्षीय हस्तकला कारीगर रूमा देवी को आईएमसी लेडीज विंग द्वारा प्रतिष्ठित जानकीदेवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने अपने प्रयासों से 22000 से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता दिलाई। उन्हें भारत में महिलाओं के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान "नारी शक्ति पुरस्कार 2018" से सम्मानित किया गया था।

इंद्रजीत सिंह

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने अलवर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह को जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान mSVEEP मोबाइल ऍप की अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए 10वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) पर सम्मानित किया।

हिंदू सिंह और मुकुट सिंह

26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस के दो पुलिसकर्मीयों ASI हिंदू सिंह और हेड कांस्टेबल मुकुट सिंह को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया।

विजयदान देथा

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, 2020 में लेखक विजयदान देथा की कहानियों पर आधारित पुस्तक "बातां री फुलवारी" के अंग्रेजी अनुवाद का लोकापर्ण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया।

राजस्थान की पद्मश्री 2020 से सम्मानित होने वाली हस्तियां

व्यक्ति	मूल स्थान	क्षेत्र
हिम्मताराम भांबू	नागौर	सामाजिक कार्य
रमजान खान उर्फ़ मुन्ना मास्टर	बगरू	जयपुर आर्ट
सुंडाराम वर्मा	सीकर	सामाजिक कार्य
उषा चौमर	अलवर	सामाजिक कार्य
अनवर खान मांगियार	जैसलमेर	जैसलमेर कला

डॉ.नंदकिशोर आचार्य एवं रामस्वरूप किसान

राजस्थान के दो साहित्यकारों बीकानेर के डॉ.नंदकिशोर आचार्य एवं हनुमानगढ़ के रामस्वरूप किसान को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया।
नंदकिशोर आचार्य को हिंदी भाषा के काव्य "छीलते हुए अपने को" के लिए
रामस्वरूप किसान को राजस्थानी भाषा में "बारीक बात" के लिए सम्मान प्राप्त किया।

राधेश्याम रंगा

एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की ओर से जोधपुर के वरिष्ठ एक्सपोर्टर राधेश्याम रंगा को सर्वाधिक निर्यात के लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया। EPCH अवार्ड समारोह में सम्मानित होने वाले देशभर के 65

एक्सपोर्टर्स की सूची में जोधपुर के तीन एक्सपोर्टर्स का नाम है। रंगा के अलावा अशोक चौहान व राहुल जौहरी को सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट से नवाजा जाएगा। केंद्रीय वस्त्र मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा पुरस्कार प्रदान किये गए।

- राधेश्याम रंगा - वुड-वेयर कैटेगरी में ट्रॉफी प्रदान की गई
- राहुल जौहरी - वुड-वेयर कैटेगरी में सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट
- अशोक चौहान - लैदर हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में सर्टिफिकेट ऑफ मैरिट

दिव्यांश सिंह पंवार

राजस्थान के राइफल शूटर दिव्यांश सिंह पंवार को इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) द्वारा अपने मुख्यालय म्यूनिख, जर्मनी में गोल्डन टारगेट अवार्ड प्रदान किया गया। दुनिया का न. 1 निशानेबाज बनने पर यह पुरस्कार दिया जाता है।

कचनार चौधरी

काठमांडू, नेपाल में आयोजित 13 वें दक्षिण एशियाई खेलों में कचनार चौधरी ने महिला शॉटपुट में कांस्य पदक जीता। महिला शाटपुट में स्वर्ण पदक भारत की आभा खटुआ ने जीता।

शीतल तोमर

काठमांडू, नेपाल में आयोजित 13 वें दक्षिण एशियाई खेलों में राजस्थान पुलिस की प्लाटून कमांडर शीतल तोमर ने सेफ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा कुश्ती में 50 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता।

श्री कृष्ण शर्मा

राजस्थान पुलिस कांस्टेबल श्री कृष्ण शर्मा ने चीन में आयोजित एशियाई ग्रैंड स्लैम मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक (91 KG भार वर्ग) जीता।

मुरलीधर प्रतिहार

बूंदी जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मुरलीधर प्रतिहार को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग (IT&C) द्वारा ग्रामीण विकास विभाग की ऑनलाइन सरकारी योजनाओं और पंचायत उद्यम पर पंचयातिराज के बेहतर निष्पादन के लिए राज्य स्तर ई- गवर्नेंस अवार्ड 2018-19 के लिए चुना गया है।

भावना जाट

भारत की रेस वॉकर भावना जाट (राजस्थान), ने रांची में 7वीं राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए सातवीं बार राष्ट्रीय पैदल यात्री चैम्पियनशिप में जीत हांसिल की। वह राजसमंद जिले के काबरा गाँव की रहने वाली है।

रवि बिश्नोई

जोधपुर के रवि बिश्नोई अंडर -19 विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ बने। वह दाएं हाथ के लेग स्पिन गेंदबाज हैं।

रुक्मेया मीणा

राजस्थान में बूंदी जिले के नैनवा उपखंड के कासपुरिया में जन्मे रुक्मैया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी के रूप में विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रुकमेया प्रयागराज में रेलवे के एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं।

सन्देश नायक

29 जून 2020 को राजीविका महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा चूरू जिले के जिला कलेक्टर सन्देश नायक को महिला उत्थान एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया।

17 फ़रवरी 2020 को घोषित किये गए महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन के 38वे अंतराष्ट्रीय व राष्ट्रिय पुरस्कार

पुरस्कार	प्राप्तकर्ता
कर्नल जेम्स टॉड अलंकरण	डॉ. नॉबर्ट पिबॉडी
हल्दीघाटी अलंकरण	राज चेंगप्पा
पन्नाधाय अलंकरण	पूरनोता दत्ता बहल
अरावली अलंकरण	गौरवी सिंघवी (तैराक)
महाराणा मेवाड़ अलंकरण	अनंत विजय, दादाराव बिल्होरे, प्रकाशचंद शर्मा
महर्षि हारीत ऋषि अलंकरण	प्रो. नीरज शर्मा, जगदीश नारायण विजय
डागर घराना अलंकरण	उस्ताद साबिर सुल्तान खान
महाराणा उदय सिंह अलंकरण	देवीलाल धाकड़
हकीम खाँ सूर अलंकरण	मनहर उदास

महाराणा कुम्भा अलंकरण	प्रो. बीएल भदानी, डॉ. प्रवीण पंड्या
महाराणा सज्जन सिंह अलंकरण	अमृत सिरोहिया
राणा पूंजा अलंकरण	डॉ. मांगीलाल परिहार
महाराणा मेवाड़ विशेष अलंकरण	पुलिस थाना चेचट, कोटा ग्रामीण

डिप्टी कमांडेंट देवेन्द्र मोहन शर्मा

अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर-2 में तैनात जयपुर निवासी डिप्टी कमाण्डेंट देवेन्द्र मोहन शर्मा को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर 14 अगस्त, 2020 को 'वीरता पुरस्कार' से सम्मानित किया गया। देवेन्द्र मोहन शर्मा को यह पुरस्कार आतंकी जाकिर मूसा के दाहिने हाथ शाकिर डार को ढेर करने में दिखाए गए अदम्य साहस और शौर्य के लिए मिला है।

रवि गांधी

पोकरण निवासी BSF DIG रवि गांधी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। डीआईजी गांधी जोधपुर स्थित राजस्थान फ्रंटियर मुख्यालय में बतौर इंटेलीजेंस चीफ व पीएसओ रहे हैं। अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने पश्चिमी सीमा पर तस्करी रोकने और सुरक्षा को लेकर कई ऑपरेशन किए थे।

गीता कुमारी

प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष राजस्थान की एकमात्र शिक्षिका बाड़मेर जिले की गीता कुमारी को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। गीता माली राजकीय शिक्षाकर्मी प्राथमिक विद्यालय सरूपाणियों मालियों का वास में शिक्षिका के पद पर कार्यरत है।

बद्रीलाल मीणा

खादी ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार के मुख्य कार्यालय मुंबई की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोरोना महामारी में अच्छे काम करने वाले तीन कार्यालयों को सम्मानित किया गया। इनमें खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के बीकानेर मण्डल ने निदेशक बद्रीलाल मीणा की कर्मठता और संवेदनशीलता के कारण प्रथम स्थान पर गोल्ड शील्ड मेडल प्राप्त किया।
मंडलीय निदेशक मीणा ने कोरोना महामारी के दौरान संस्थाओं के साथ जुड़कर मास्क वितरण, भोजन किट वितरण, साबुन वितरण, बच्चों के लिए दूध वितरण, प्रवासी परिवारों के लिए कार्यक्रम बनाकर अहम भूमिका निभाई। उन्होंने राजस्थान राज्य की जनता को रोजगार से जोडने़ का सराहनीय कार्य भी किया है।

जांच में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक-2020 से राजस्थान के छह पुलिसकर्मी सम्मानित

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिया जाने वाला 'जाँच में उत्कृष्टता के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का पदक-2020' से 121 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया है। इनमें राजस्थान के छह पुलिसकर्मी शामिल हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने आपराधिक मामलों की जाँच के दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2018 में गृहमंत्री पदक की शुरुआत की थी।

राजस्थान से सम्मानित होने वाले पुलिसकर्मी:

- पुलिस उप अधीक्षक प्रशांत कौशिक
- पुलिस निरीक्षक मुनिन्दर सिंह
- राजेश यादव
- पवन कुमार चौबे
- सन्तरा मीणा
- उप-निरीक्षक मलकियत सिंह

मेघा हर्ष

बीकानेर की मेघा हर्ष को दुनिया में सबसे बड़ी ड्राइंग के लिए genius book of record से सम्मानित किया गया है।

नियुक्तियां

धर्मपाल जालोरी

डॉक्टर धर्मपाल जारोली राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 2018 में तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बीएल चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद से यह पद रिक्त था।

सी.पी.जोशी

29 जनवरी, 2020 को संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सी.पी.जोशी को संविधान के पीठासीन अधिकारियों की शक्तियों की समीक्षा करने के लिए बनाई गई तीन सदस्यीय समिति का सभापति नियुक्त किया गया। इस समिति में ओडिशा विधानसभा के अध्यक्ष सूज्या नारायण पेट्रो और कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कांगड़ी सदस्य होंगे।

विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी द्वारा 2020 -21 के लिए गठित की गई विभिन्न समितियाँ और उनके सभापति

समिति	सभापति
जनलेखा समिति	गुलाबचंद कटारिया
प्राक्कलन समिति (क)	राजेन्द्र पाराक
प्राक्लन समिति (ख)	दयाराम
राजकीय उपक्रम समिति	हेमाराम चौधरी
नियम समिति	सी.पी. जोशी
सदाचार समिति	दीपेन्द्र सिंह
स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थाओं संबंधी समिति	डॉ. राजकुमार शर्मा
विशेषाधिकार समिति	शकुंतला रावत
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	नरेन्द्र बुडानियां
याचिका समिति	अर्जुनलाल जीनगर

श्री राजीव स्वरूप

- 2 जुलाई 2020 को राज्य सरकार द्वारा श्री राजीव स्वरूप को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) थे। उन्होंने डी. बी. गुप्ता का स्थान लिया है।
- श्री डी.बी.गुप्ता को मुख्यमंत्री सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।

आशुतोष शर्मा

आशुतोष शर्मा को राजस्थान राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।

अनिल चौधरी

9 जुलाई 2020 को हुए राजस्थान वालीबॉल संघ के चुनाव में नवीन यादव को संघ का अध्यक्ष चुना गया। राजस्थान वालीबॉल संघ महासचिव - रामावतार जाखड़

गोविन्द सिंह डोटासर

शिक्षामंत्री गोविन्द सिंह डोटासर, 14 जुलाई 2020 को प्रदेश कांग्रेस (PCC) के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने सचिन पायलट का स्थान लिया।

जोस मोहन

3 जुलाई 2020 को IPS अधिकारी जोस मोहन को जोधपुर के नए पुलिस कमिश्नर पद पर नियुक्त किया गया।

राज्य में जयपुर व जोधपुर दो कमिश्नरेट है।

प्रवीण गुप्ता

3 जुलाई 2020 को IAS अधिकारी प्रवीण कुमार को राज्य का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रवीण गुप्ता ने आनंद कुमार स्थान लिया है।

- राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष - प्रेमसिंह महरा

के.सी.वर्मा

6 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के.सी.वर्मा ने राजस्थान वित्त निगम के प्रबंध निदेशक का कार्यभार संभाला है।

इंद्रजीत महांति

इंद्रजीत महांति, राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए है। वे राजस्थान के 37वें मुख्य न्यायाधीश है। उन्होंने एस.रविंद्र भट्ट का स्थान लिया है।

जनार्दन सिंह गहलोत

11 जुलाई 2020 को जनार्दन सिंह गहलोत को राजस्थान ओलम्पिक संघ (ROA) का अध्यक्ष चुना गया। वे 1981 से लगातार इस पद पर स्थापित है।

- **ROA चेयरमैन** - प्रमोद जादम
- **ROA महासचिव** - अरुण कुमार सारस्वत

नवीन यादव

जुलाई 2020 में नवीन यादव को राजस्थान बॉडीबिल्डिंग संघ का अध्यक्ष चुना गया।

- **राजस्थान बॉडीबिल्डिंग संघ सचिव** - राजेश यादव

डॉ.पी.सी.पंचारिया

डॉ.पी.सी.पंचारिया ने 14 जुलाई 2020 को झुंझुनू के पिलानी स्थित केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसन्धान संस्थान (CEERI) में निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया।

अरुण मिश्रा

अरुण मिश्रा ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का पदभार संभाला। उन्होंने 1 अगस्त 2020 को सुनील दुग्गल का स्थान लिया।

प्रो.विनोद कुमार सिंह

25 जुलाई, 2020 को प्रो.विनोद कुमार सिंह को महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर का कुलपति नियुक्त किया गया है। प्रो.विनोद कुमार सिंह IIMT विश्वविद्यालय, मेरठ के कुलपति थे।

मानवेंद्र सिंह जसोल

राजस्थान फुटबॉल संघ के लिए चुनाव में मानवेंद्र सिंह जसोल को अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चुना गया है। 23 जुलाई, 2020 को राजस्थान फुटबॉल संघ के निर्वाचन अधिकारी हरिवल्लभ बोहरा ने उनके निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की गई।

IAS अधिकारी टीना डाबी

IAS अधिकारी और गंगानगर जिला परिषद की CEO टीना डाबी को अंतर्राष्ट्रीय संस्था BRICS CCI(चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज) यंग लीडर्स (इंडिया) इनिशिएटिव समिति का मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। टीना डाबी, तीन साल (2023 तक) के लिए पदभार संभालेंगी। टीना डाबी देश की पहली आईएएस अधिकारी है जो इस पद पर नियुक्त की गई है।

BRICS CCI भारत सरकार के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत निकाय है, और NITI Aayog (भारत सरकार के उच्चतम नीति-निर्माण निकाय) के साथ सूची में सम्मिलित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। ब्रिक्स सीसीआई ने पांच देशों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के युवाओं को जोड़ने के लिए एक युवा नेताओं की पहल शुरू की है।

डॉ.अनुला मौर्य

डॉ.अनुला मौर्य को राज्य वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड के प्रारूपण के लिए राज्य समिति की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

अन्य

रूमा देवी

16 फ़रवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आयोजित इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को बतौर स्पीकर सम्बोधित करने वाली राजस्थानी महिला है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण तथा प्रभावी नेतृत्व पर व्याख्यान दिया।

अतिका शर्मा

भीलवाड़ा की अतिका शर्मा ने "मिसेस यूके 2020" में फाइनलिस्ट में जगह बनाई।

इरफान अली गौड

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी 64 वर्षीय इरफान अली गौड का 23 जुलाई, 2020 को जयपुर में कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। गौड सीकर साइकिलिंग संघ के अध्यक्ष व हैंडबाल संघ के सचिव भी रहे है। उनकी स्मृति में राज्य sub junior (boys) handball के 'बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार' शुरू किया जाएगा।

डॉ.अजय यादव

सीएम अशोक गहलोत ने होम्योपैथिक डॉक्टर अजय यादव द्वारा लिखित पुस्तक "मिस्ट्री ऑफ कोरोना" का विमोचन किया।

सीमा हिंगोनिया

- 6 जुलाई, 2020 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा हिंगोनिया द्वारा लिखित पुस्तक 'सेव यूथ सेव नेशन' का विमोचन किया गया।
- पुस्तक का विमोचन पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने किया।
- इस पुस्तक में युवाओं के लिए बने विभिन्न कानूनों जैसे पोक्सो एक्ट, जे.जे.एक्ट ,रैगिंग एक्ट, साइबर अपराध आदि के बारे में लिखा है।

चर्चित स्थान

IIT जोधपुर

IIT जोधपुर ने औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए राजस्थानी मिट्टी से बना ठोस स्नेहक विकसित किया है जिससे मशीनों का घिसना कम होगा।यह स्नेहक बहुत कम घर्षण के साथ -50 और 1100 डिग्री के बीच के तापमान में अच्छी तरह से काम करता है।

MBM कॉलेज, जोधपुर

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज को आगामी सत्र से पेट्रोलियम और भू-विज्ञान विभाग खोलने की भी मंजूरी दी गई है। जिसका उद्देश्य कच्चे तेल से संबंधित क्षेत्रों में इंजीनियरों की बढ़ती मांग को पूरा करना होगा। यह झुंझुनू में राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बाद राज्य का दूसरा विषय विशिष्ट विश्वविद्यालय होगा।

जयपुर एयरपोर्ट

जयपुर हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण में प्रति वर्ष 50 लाख से अधिक यात्रियों के यातायात के साथ सबसे स्वच्छ और सबसे सुरक्षित हवाई अड्डे की श्रेणी में स्वछता पुरस्कार 2019 में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हवाई अड्डा अधिकारीयों को इस संबंध में प्रशस्ति पुरस्कार प्रदान किये गए। इस श्रेणी में कोलकाता शीर्ष स्थान पर जबकि चेन्नई दूसरे स्थान पर रहा।
ग्राहक संतुष्टि में उदयपुर एयरपोर्ट ने देशभर में दूसरा स्थान अर्जित किया तथा जोधपर 8वें स्थान पर रहा।

जयपुर परकोटा

5 फरवरी, 2020 को यूनेस्को प्रमुख आन्द्रे अजोले ने अल्बर्ट हॉल पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान जयपुर परकोटे को विश्व विरासत (world haritage) का प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

पूर्णिमा यूनिवर्सिटी कैम्प्स, जयपुर

2-6 मार्च 2020 तक जयपुर के पूर्णिमा यूनिवर्सिटी कैम्प्स में सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। 47 वर्ष बाद जयपुर में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

- गोल्ड मैडल - इंडियन रेलवे की पुरुष व महिला टीम
- सिल्वर मैडल -सेना व हिमाचल प्रदेश

जैसलमेर

राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन (NTPC) व सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (SECI) द्वारा जैसलमेर जिले में राज्य का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क विकसित किया जायेगा। 12 जून, 2020 को मुख्यमंत्री ने इस परियोजना को सैद्धान्तिक सहमति दी है।

बनस्थली विद्यापीठ,टोंक

बनस्थली विद्यापीठ राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद(National Assessment and Accreditation Council,NAAC) द्वारा A ++ ग्रेड प्राप्त करने वाला राजस्थान का पहला संस्करण बन गया है। NAAC का मूल्यांकन सात मानदंडों के आधार पर किया जाता है और बनस्थली ने अपनी समग्र उत्कृष्टता को दर्शाते हुए 90% से अधिक अंक अर्जित किए। विद्यापीठ ऐसी संस्था है जो लड़कियों को शिशु कक्षा से लेकर पी.एच.डी. स्तर तक की शिक्षा प्रदान करती है।

भरतपुर

3 मार्च, 2020 को ऊर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला ने भरतपुर संभाग में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री बी.डी.कल्ला ने राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले उद्यमिता, वैज्ञानिक पत्रकारिता, नवाचार, युवा वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए प्रदेश में STRIDE (Science Technology, Research, Innovation, design, Enterpreneur) पुरस्कार की घोषणा की है।

खण्डेला, सीकर

सीकर जिले के खण्डेला उपखण्ड के गांव रोहिल व सुहागपुरा और इनके आप-पास के क्षेत्र में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग(DAE) ने यूरेनियम का बड़ा भंडार खोजा है। इसमें 10 हजार टन यूरेनियम के भंडार पाए जाने की पुष्टि हुई है। सीकर-झुंझुनूं की सीमा से लगते इन गाँवो में 22 साल से चल रहे सर्वे के अनुकूल परिणाम सामने आने पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया(UCIL) ने यहां से यूरेनियम निकालने की तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान में यूरेनियम का यह पहला प्रोजेक्ट है। यह आंध्र प्रदेश के तुम्मलपल्ली, चित्रियाल और पेड्डागट्टू विस्तार परियोजना के बाद देश की चौथी बड़ी यूरेनियम खान है। वर्तमान में 400 फीट नीचे उपस्थित यूरेनियम के स्रोत के लिए नई सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से यूरेनियम नेशनल फ्यूल कॉर्पोरेशन(NFC) भेजा जाएगा।

जैसलमेर और बाड़मेर में नए जल भंडार

तेल के बाद, अब एक और खोज से जैसलमेर और बाड़मेर के लोगों का जीवन बदलने वाला है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (PNG) मंत्रालय द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के अनुसार जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में 482 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध होने का अनुमान है। जो अगले 100 वर्ष तक बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर समेत पश्चिमी

राजस्थान को पेयजल उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय के इस एक प्रयास से राज्य की किस्मत बदलने वाली है।
भारत के लिए अनुमानित वार्षिक घरेलू और पेयजल की मांग 2025 तक 55 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) और 2050 तक 90 (BCM) है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष:

खोजे गए जलस्तर थम्बली, फतेहगढ़ और जगदिया जल भंडार का हिस्सा हैं, जिनमें पानी की अनुमानित उपलब्धता है:

- थम्बली - 110 BCM
- फतेहगढ़ - 82 BCM
- जगदिया - 290 BCM

यह पानी खारा है और इसका TDS (Total Dissolved Solids) 1,000 से 10,000 TDS प्रति लीटर के बीच है जबकि मानक नियमों के अनुसार पीने के पानी के TDS की अधिकतम अनुमेय सीमा 600 TDS प्रति लीटर होती है।

पानी की उपलब्धता की गहराई:

- थम्बली: 100-1100 मीटर
- फतेहगढ़: 150-1500 मीटर
- जगदिया: 0-800 मीटर

हालांकि, पानी की लवणता इस परियोजना के लिए एक बड़ी चुनौती है। थम्बली जलभंडार को, बड़े पैमाने पर अलवणीकरण परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है।

उदयपुर व जयपुर

भारतीय रेलवे के हाइस्पीड कॉरिडोर (बुलेट ट्रेन) के लिए चिन्हित दिल्ली-अहमदाबाद रूट में प्रदेश के दो शहरों उदयपुर व जयपुर को शामिल किए जाने की परियोजना पर कार्य शुरू किया गया है। दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद का यह रुट 886 किलोमीटर का होगा।

नोख (बीकानेर)

राजस्थान में जोधपुर जिले के भड़ला सोलर पार्क के बाद जैसलमेर जिले के नोख में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड (RRECL) की ओर से

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। इस पार्क की क्षमता 925 मेगावाट होगी। नई सौर ऊर्जा नीति के अनुसार अगले 5 साल में प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन छह गुना तक बढ़ाना है।

- **भड़ला सोलर पार्क** - 2250 मेगावाट
- **नोख सोलर पार्क** - 925 मेगावाट

महाजन फील्ड फायरिंग रेंज (बीकानेर)

भारतीय सेना के स्ट्राइक कोर नंबर 2 के 40000 से अधिक सैनिकों द्वारा अपना फायर पावर कौशल परिक्षण तथा युद्धाभ्यास 'खडग शक्ति' बीकानेर जिले के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्न किया गया।

मेनार (उदयपुर)

इम्पोर्टेन्ट बर्ड एरिया (IBA) के रूप में नामित उदयपुर का मेनार देशी-विदेशी पक्षियों का आश्रय स्थल है। इसे बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है ।

- **IBA साइट कोड:** IN-RJ-30
- **IBA मानदण्ड:** A1
- **संरक्षण:** स्थानीय ग्रामीणों के स्तर पर

गाँव 'पाँचला सिद्धा', नागौर

जनवरी 2020 में नागौर के 'पाँचला सिद्धा' गाँव में अन्तर्राष्ट्रीय महिला उत्सव 'माँ' का आयोजन किया गया इसमें 12 देशों की महिलाएँ शामिल हुई। जिसमे कुछ चर्चीत महिलाएं जैसे अमेरिकी लेखिका एलिजाबेथ गिलबर्ट और नारी शक्ति पुरस्कार 2019 की विजेता रूमा देवी भी शामिल है। पिछले तीन वर्ष से 'योगा' और मौसम का महत्व समझने के लिए इसका आयोजन हो रहा है। मनोवैज्ञानिक 'श्रीजन सीता' योगा प्रोग्राम की डायरेक्टर थी।

दादिया, जयपुर

जयपुर के दादिया गाँव को राजस्थान के पहले जैविक गाँव (Organic Village) के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। केन्द्र की प्रधानमंत्री आदर्श गांव योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana) की तर्ज और वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य से यह पहल की गई है।

सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर

राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के प्रथम प्लाज़्मा बैंक की स्थापना जयपुर के सवाई मान सिंह चिकित्सालय में की जा रही है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने 24 जुलाई 2020 को प्लाज़मा बैंक का पोस्टर जारी करते हुए कोरोना वारियर्स से अधिक से अधिक प्लाज़्मा दान करने की अपील की है।

RISU जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने 'नॉलेज सिटी' परियोजना के तहत सीकर रोड पर स्थित चोप गांव में राजस्थान ILD कौशल विश्वविद्यालय (RISU) की स्थापना के लिए 23 एकड़ जमीन मुफ्त में आवंटित की है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में पचपदरा गाँव के पास पेट्रोलियम रिफाइनरी के निकट 'ऊर्जा गाँव' विकसित करने के उद्देश्य से 30 एकड़ जमीन मुफ्त में विश्वविद्यालय को आवंटित की थी।

MPUAT, उदयपुर

उदयपुर, के महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी ऑफ़ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी (MPUAT) और बीकानेर, के राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ़ वेटेरिनरी एंड एनिमल साइंस (RAJUVAS) के बीच पांच साल के लिए जैविक खेती, पशुपालन, और अच्छी कृषि प्रथाओं के क्षेत्र में संयुक्त सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन किया गया है।

बाड़मेर में खोजे गए शार्क के दांतों के जीवाश्म

दिल्ली विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने बाड़मेर जिले में बड़ी संख्या में शार्क के दांतों के जीवाश्म पाए हैं, जो साबित करते हैं कि लगभग 58 मिलियन (साढ़े पांच करोड़) वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र समुद्र के नीचे था। बाड़मेर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर स्थित गिरल लिग्नाइट खदान के पास लगभग 58 मिलियन वर्ष पुरानी पेलियोसीन चट्टानों में ये जीवाश्म पाए गए है। दांतों के आधार पर शोधकर्ताओं ने नौ भिन्न प्रकार की शार्क की पुष्टि की है। इस शोध से आद्र्र तटीय परिस्थितियों, जलवायु परिस्थितियों के संदर्भ में पर्यावरणीय परिवर्तनों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त हुई है।
इस से पहले भी जैसलमेर के सुल्ताना व बांधा गांव में वैज्ञानिकों ने करीब 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्मों को खोज की थी। इनमें आदिकालीन व्हेल और शार्क के दांत, मगरमच्छ के दांत और कछुए की हड्डियों के जीवाश्म पाए गए थे, जो इस बात को प्रमाणित करते है की राजस्थान में जहाँ अब रेगिस्तानी इलाके है वहां कभी समुद्र रहा होगा, जो बाद में जलवायु परिवर्तन के कारण रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया।

राजस्थान

देश के प्रमुख शहरों को जयपुर से हवाई रूट के माध्यम से जोड़ने हेतु राज्य सरकार को 16 मार्च, 2020 को बेस्ट प्रो-एक्टिव स्टेट फ्री अवॉर्ड मिला है। केन्द्र सरकार की शुरू की गई उड़ान योजना में हवाई रूट शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों को कई तरह की सहूलियतें दी गई हैं। नागरिक उड्यन मंत्रालय द्वारा हैदराबाद में आयोजित विंग्स-2020 फ्लाइंग फॉर ऑल समिट में राजस्थान सरकार को यह अवॉर्ड प्रदान किया गया। प्रदेश में उड़ान योजना लागू करने के लिए एमओयू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है साथ ही राज्य सरकार ने उड्डयन कंपनियों को सभी सूहिलयतें भी प्रदान की है।

रामगढ़ गाँव, बारां (देश का पहला जिओ हैरिटेज साइट)

उल्का पिण्डों की बारिश के बाद बने चार किमी.चौड़े गढ्ढे (क्रेटर) को जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (GST) ने। देश का पहला भू-विरासत स्थल घोषित किया है। बारां जिले के रामगढ़ गाँव में उल्का पिण्डों की बारिश के बाद बने चार किमी. चौड़े गढ्ढे (क्रेटर) को जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया (GSI) ने देश का पहला भू-विरासत स्थल घोषित किया है। भारतीय सांस्कृतिक निधि के प्रस्ताव को GSI ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अभी तक देश में 32 राष्ट्रीय भू-स्मारक घोषित है परन्तु किसी स्थल को पहली बार भू-विरासत का दर्जा दिया गया है। रामगढ़ गाँव पिछले 147 वर्षों से अपनी इस पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था।

जावर [उदयपुर]: उदयपुर स्थित जावर का दुसरे भू-विरासत स्थल के रूप में चयन किया गया है।

सांचौर, राजस्थान

राजस्थान के जालोर जिले के सांचोर कस्बे में आसमान से 2.788 किलोग्राम वजनी उल्कापिंड जैसा पत्थर आकर गिरा। करीब चार से पांच फीट की गहराई में जाकर यह टुकड़ा धंस गया यह काले रंग की चमकीली धातु जैसा नजर आ रहा है।

उल्कापिंड

आकाश में कभी-कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का कहते हैं। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे उल्कापिंड कहते हैं।

महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने 23 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राज्यपाल महोदय ने विश्वविद्यालय में बनने वाले संविधान पार्क का भी शिलान्यास किया।

आयुर्वेद विभाग का मेडिट्यूरिज्म सेन्टर, कुम्भलगढ़

आयुर्वेद मंत्री डॉ.रघु शर्मा के निर्देशानुसार उदयपुर सम्भाग के कुम्भलगढ़ में आयुर्वेद विभाग का 'मेडिट्यूरिज्म सेन्टर' बनाया जाएगा। सेन्टर की स्थापना के लिए की जा रही तैयारियों के सम्बन्ध में आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग की शासन सचिव डॉ.वीना प्रधान ने 18 अगस्त, 2020 को उदयपुर सम्भाग के प्रवास के दौरान कुम्भलगढ़ में चयनित स्थान का निरीक्षण किया।

इस मेडिटयूरिज्म सेन्टर में आयुर्वेद की बहिरंग व अन्तरंग चिकित्सा विशेषज्ञ चिकित्सा यथा पंचकर्म, क्षारसूत्र आदि, यूनानी व होम्योपैथी चिकित्सा की ओपीडी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा वैलनेस सेन्टर का संचालन, हर्बल गार्डन आदि की सेवाएँ दी जाएंगी।

कोटा प्लाज्मा बैंक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने 1 अगस्त, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटा मेडिकल कॉलेज के 'प्लाज्मा बैंक' का शुभारम्भ किया। जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज के बाद यह प्रदेश का दूसरा प्लाज्मा बैंक है। 200 यूनिट की क्षमता वाले इस प्लाज्मा बैंक द्वारा कोरोना के गम्भीर मरीजों का समुचित उपचार किया जायेगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जोधपुर शहर को मिला फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड

केन्द्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने 20 अगस्त, 2020 को जनवरी में आयोजित हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के परिणाम घोषित किये। जिसमें जोधपुर शहर को 29वीं रैंक प्राप्त हुई है। जबकि विगत वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में जोधपुर शहर को 243वीं रैंक मिली थी। इस प्रकार 214 रैंक के सुधार के साथ जोधपुर शहर को 'फास्टेस्ट मूविंग शहर' का अवॉर्ड प्राप्त हुआ है। जोधपुर शहर को वर्ष 2018 में 188वीं रैंक प्राप्त हुई थी।
सिटीजन फीडबैक में शहर की जनता ने अपनी सकारात्मक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शहर को सिटीजन फीडबैक में राजस्थान में नम्बर 1 बनाया है।इस वर्ष जोधपुर शहर को 6,000 में से कुल 3,615 अंक प्राप्त हुए जबकि वर्ष 2019 में हुए सर्वे में इसे 2,091 अंक प्राप्त हुए थे। जोधपुर शहर को फील्ड ऑब्जेर्वेशन में 1,500 में से 1,045 अंक प्राप्त हुए हैं।
जयपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 में 28वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। विगत वर्ष 2019 के सर्वेक्षण में जयपुर की रैंकिग 44वीं थी।

कोटा स्मार्ट सिटी के तहत् प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण

17 अगस्त, 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटा विकास न्यास के स्मार्ट सिटी के तहत् प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। उक्त शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा कुल 1,056 करोड़ लागत के 12 कार्यों का शिलान्यास एवं वरिष्ठ नगर नियोजक के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया।

मुख्यमंत्री द्वारा जिन विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया उनमें से प्रमुख का विवरण निम्नानुसार है:

देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना

कोटा शहर में 300 करोड़ रू लागत से देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है
इस योजना में पशुपालकों को अपने पशुओं के पास रहने और उनकी देखभाल करने के लिए भू-खण्डों तथा आवासीय भवनों का आवंटन किया जायेगा। इस योजना से शहरवासियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी।

चम्बल रिवर फ्रंट विकास योजना

चम्बल रिवर फ्रंट विकास योजना एक ऐसी नायाब परियोजना है, जो कोटा शहर को आधुनिक स्थापत्य एवं वास्तु कला के मानचित्र पर पूरी दुनिया में प्रसिद्धि दिलाएगी।
307 करोड़ रूपए लागत की इस योजना में 6 किमी लम्बे हैरिटेज रिवर फ्रन्ट का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पूरे राजस्थान की संस्कृति एवं स्थापत्य कला के समन्वय का बेहतरीन प्रदर्शन होगा। प्रस्ताव के अनुसार, इस परियोजना में कई बगीचों और कैफे-रेस्टोरेंट आदि का निर्माण किया जाएगा तथा जगह-जगह पर देश-प्रदेश की महान विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित कर उसे आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।

पर्यावरण

मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व क्षेत्र के आस-पास Eco-Sensitive Zone

जनवरी 2020 में, MOEFCC (Ministry of Environment, Forest and Climate Change) ने कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के चार जिलों को कवर करते हुए 759.99 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिज़र्व (MHTR) अभयारण्य के क्षेत्र में से 248.70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को Eco-Sensitive Zone के दायरे में शामिल किया है। इसमें अभयारण्य के आसपास के 1 किमी के क्षेत्र को Eco-Sensitive Zone घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। नए अधिनियम के अनुसार अभयारण्य के आसपास के 75 गांव प्रभावित होंगे। जिन ग्रामों की राजस्व जमीन मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई है उनका अब व्यवसायिक रूप में भू-उपयोग परिवर्तन नहीं हो सकेगा वे गांव अब राजस्व गांव ही रहेंगे। उनकी जमीनें जो रोड पर आ रही हैं वे अब व्यवसायिक रूप में उपयोग में नहीं ली जा सकेंगी।

गोडावण CMS सूचि में शामिल

राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण को 'प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण' (Conservation of Migratary Specie-CMS) सूची में शामिल किया गया है। 15-22 फरवरी, 2020 तक गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए 13वें कोप शिखर सम्मेलन में भारत के प्रस्ताव पर एशियाई हाथी,गोडावण तथा बंगाल फ्लोरिकन को विलुप्त हो रहे जीवों की अन्तर्राष्ट्रीय सूची में शामिल कर लिया गया है। 13वें कोप शिखर सम्मेलन का शुभंकर गोडावण ही था।

CMS-COP-13

- CMS-COP-13 का विषय Migratory species connect the planet and together we welcome them home अर्थात “प्रवासी प्रजातियाँ पृथ्वी को जोड़ती हैं और हम मिलकर उनका अपने घर में स्वागत करते हैं।”
- भारत सरकार ने गोडावण पर विशेष डाक टिकट भी जारी किया है the Great Indian Bustard - the mascot of COP13
- CMS COP13 के लिए शुभंकर,"Gibi - द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड” एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति है जिसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत सबसे अधिक संरक्षण दिया गया है।
- CMS COP13 का प्रतीक चिन्ह 'कोलम' दक्षिणी भारत की एक पारंपरिक कला से प्रेरित है इस चिन्ह में कोलम कला का उपयोग प्रमुख प्रवासी प्रजातियों को चित्रित करने के लिए किया गया है जैसे भारत का अमूर बाज़, हम्पबैक व्हेल और समुद्री कछुआ।

CMS

- CMS एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है, इसे बॉन कन्वेंशन (Bonn Convention) के नाम से भी जाना जाता है।
- वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nation Environment Programme-UNEP) के तहत जर्मनी के बॉन (Bonn) शहर में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- आधिकारिक रूप से यह समझौता वर्ष 1983 में लागू हुआ और वर्तमान में इसके 130 सक्रिय सदस्य (यूरोपियन यूनियन व 129 अन्य देश) हैं।
- CMS का मुख्यालय बॉन (Bonn) जर्मनी में स्थित है।

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- भारत वर्ष 1983 से इस सम्मेलन का सदस्य रहा है।तथा भारत को अगले तीन वर्ष के लिए इस कांफ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है
- भारत कई प्रवासी जानवरों और पक्षियों का अस्थायी घर है। अमूर फाल्कन, बार हेडेड घीस, ब्लैक नेकलेस क्रेन, मरीन टर्टल, डूगोंग, हंपबैक व्हेल इत्यादि इनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण प्रजातियाँ हैं।
- भारतीय उप-महाद्वीप प्रमुख पक्षी फ्लाईवे नेटवर्क का हिस्सा है। इसे मध्य एशियाई फ्लाईवे (The Central Asian Flyway - CAF) भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्कटिक एवं हिन्द महासागर के मध्य का क्षेत्र आता है।
- इस क्षेत्र में जलीय पक्षियों की 182 प्रजातियों की कम-से-कम 279 आबादी पाई जाती है, जिसमें से 29 प्रजातियाँ वैश्विक रूप से संकटापन्न स्थिति में हैं।
- साइबेरियन क्रेन (1998), मरीन टर्टल (2007), डूगोंग (2008) और रैप्टर (2016) के संरक्षण और प्रबंधन पर CMS के साथ गैर कानूनी रूप से बाध्यकारी MOU पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं।

क्रेप्टिवे ब्रीडिंग प्लानिंग - राज्य पक्षी गोडावण के अंडे से चूज़े बनने की प्रक्रिया

चम्बल नदी

केन्द्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में चम्बल और उसकी सहायक नदियों को शामिल किया गया है इसके अंतर्गत चम्बल व उसकी सहायक नदियों की साफ़-सफाई तथा दोनों ओर पौधरोपण करके मृदा संरक्षण व वन क्षेत्र को विकसित करना शामिल है। 625 वर्ग किमी.में फैला राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभयारण्य का 284 किमी. का क्षेत्र इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा।इस परियोजना में सम्मिलित की गई नदियां:

1. चंबल नदी
2. बूंदी की मेज नदी

3. बारां की परवन और पार्वती नदी
4. सवाई माधोपुर की बनास नदी
5. गम्भीरी नदी

राज्य वन्यजीव मंडल

7 फ़रवरी 2020 को राजस्थान सरकार ने वन्यजीव परियोजनाओं और संरक्षित क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन के लिए राज्य वन्यजीव मंडल (state wildlife board) का गठन किया जिसके अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे। इसके अतिरिक्त इस समिति में 13 अन्य सदस्यों को मनोनीत किया गया है जिनमे 3 सदस्य गैर सरकारी संस्थाओ से और 10 बतौर पर्यावरणविद ,संरक्षणकर्ता ,विज्ञानी होंगे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। राजस्थान राज्य वन्यजीव बोर्ड का गठन वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972(केंद्रीय अधिनियम 53-1972) की धारा-6 के तहत किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित अधिनियम और दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को वन्यजीव बोर्ड बनाना और उन्हें अनुमोदित करवाना अनिवार्य है।
बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वह वन्यजीवों से संबंधित नीतियों के निर्माण पर ध्यान दे और यह सुनिश्चित करे कि पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण किया जा रहा है । साथ ही बोर्ड अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि अतिक्रमण या अवैध गतिविधियों के कारण वन्यजीव और वन को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचे। दिशानिर्देशानुसार वर्ष में कम से कम दो बार बोर्ड मीटिंग का होना जरुरी है। 13 सदस्यीय बोर्ड वन्यजीवों के साथ साथ जंगल के आदिवासियों और अन्य निवासियों की आवश्यकताओं के सामंजस्य के लिए किए जाने वाले उपायों पर भी विचार कर सकता है।

राज्य सरकार द्वारा निर्माण कार्य के लिए M-Sand उपयोग के दिशा निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बजरी के खनन पर रोक लगाने के बाद बजरी आपूर्ति के संकट को मेनुफेक्चरिंग सैंड (M-Sand) या कृत्रिम रेत से खत्म किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार M-Sand न केवल बजरी का बेहतर विकल्प हैं, बल्कि यह नदी बजरी से कहीं अधिक मजबूत भी हैं। राजस्थान के विभिन्न जिलों में खनन से मिनरल निकालने के पश्चात् बचे अपशिष्ट के पहाड़ खड़े हो गए हैं। इस अपशिष्ट को M-Sand में परिवर्तित करके बजरी की समस्या खत्म की जा सकती है।

M-Sand की जानकारी तथा लाभ:

- M-Sand अर्थात मेनुफेक्चरिंग सैंड या कृत्रिम रेत
- राजस्थान के विभिन्न जिलों में ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, बेसाल्ट, सिलिका और बलुआ पत्थर के खनन पर बचे अपशिष्ट से इसे प्राप्त किया जा सकता है।

- DMG द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार राज्य को अपनी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए प्रतिवर्ष 37 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) रेत की आवश्यकता होती है तथा "M-Sand के निर्माण के लिए कच्चे माल का अनुमानित भंडार 800 (MMT) है।
- पर्यावरण संरक्षण के लिए M-Sand नदी बजरी का एक बेहतर विकल्प है सरकार को जल्द से जल्द इसके उपयोग की अनुशंषा करनी चाहिए।

कुंभलगढ़ अभयारण्य में दिखी दुर्लभ प्रजाति की लाइलक सिल्वरलाइन तितली

प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन की पर्यावरण वैज्ञानिक डॉ स्वाति किड्डूर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के शोधार्थी उत्कर्ष प्रजापति ने दक्षिणी राजस्थान के कुंभलगढ़ अभयारण्य में स्लॉथ बीयर की पारिस्थितिकी पर अपने शोध के दौरान दुर्लभ लाइलक सिल्वरलाइन नामक तितली को खोजा है। इस प्रजाति की खोज 1880 के दशक में की गई थी, और इसे बेंगलुरु में मात्र एक की संख्या में ही देखा गया था।

67 वर्ष बाद थार मरुस्थल में दिखी डेजर्ट ग्रिजलड स्कीपर तितली

राजस्थान के थार मरुस्थल में जैसलमेर में विश्व की विलुप्त प्रजाति की तितली 'डेजर्ट ग्रिजलड स्कीपर' जिसका वैज्ञानिक नाम 'स्पिलिया डोरिस इवानिडा' है को 67 सालों बाद फिर से देखा गया। इसे सिंध स्किपर के नाम से भी जाना जाता है। इस तितली को अंतिम बार गुजरात के डीसा में वर्ष 1949 में देखा गया था।

डेजर्ट नेशनल पार्क में लोमड़ियाँ त्वचा रोग से संक्रमित

जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में रेगिस्तानी लोमड़ी में संक्रामक त्वचा रोग (Mange Skin Disease) फ़ैल रहा है, जिसके बाद वन विभाग और पशु पालन विभाग को ऊँटों में इस बीमारी का ध्यान रखने के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

मेंज (Mange) नामक यह बीमारी परजीवी घुन के कारण फैलती है, और स्तनधारियों में संक्रामक त्वचा रोग का रूप ले लेती है। लोमड़ियों, कुत्तों, भेड़ों, भालू और ऊँटों में इस बीमारी के संक्रमण से भूख नहीं लगती, बाल झड़ जाते है तथा खुजली के कारण होने वाले घाव में कीड़े लगने के बाद उनकी मौत हो जाती है। इसे स्थानीय भाषा में पों या कुत्ता खुजली कहा जाता है.

संक्रमण के प्रमुख क्षेत्र सावंता, नेडान, सनावाड़ा, लाठी, भादरिया, ओढानिया-चाचा, धोलिया (सभी पोखरण ब्लॉक में) और सम, सुदासरी, गंगा, बिध, जमरा, निम्बा और कुछ आसपास के क्षेत्र (सभी डेजर्ट नेशनल पार्क हैं)।

चमगादड़ के लिए कानूनी संरक्षण

कोरोना संकट की वजह से लोगों में चमगादड़ के प्रति काफी गलतफहमियां पैदा हो गई हैं। कई क्षेत्रों में चमगादड़ को मारने और भगाने की घटनाएं सामने आने के बाद राजस्थान के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर ने सभी टाइगर रिजर्व और जिला स्तर के वन अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी कर क्षेत्र में लोगों को प्रकृति में चमगादड़ के अहम रोल के बारे में शिक्षित कर चमगादड़ को लेकर फैल रही गलतफहमियों को दूर करने और इसे मारे जाने की स्थिति में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

- कोविद -19 महामारी के बीच राजस्थान इन स्तनधारियों की रक्षा करने वाला कर्नाटक के बाद, दूसरा राज्य बन गया है।
- चमगादड़ भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची V के तहत आते हैं और आज तक उन्हें मारने पर सजा का कोई प्रावधान नहीं था।

दिल्ली में साल्वाडोर के पेड़

पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले साल्वाडोरा के पेड़, जिन्हें स्थानीय तौर पर पीलू या रेगिस्तान के अंगूर के नाम से भी में जाना जाता है, जल्द ही नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में देखा जाएगा। इस पेड़ का फल न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि कई औषधीय गुणों युक्त भी होता है। गुरुग्राम के IMG संस्थान ने जैसलमेर के सांवता गांव के निवासी किसान सुमेर सिंह भाटी से इसके बीज मंगवाए हैं इन्हे पौधशाला में लगाकर इसके पौधों को संसद भवन के गार्डन व अन्य महत्वपूर्ण गार्डन और बाग-बगीचों में लगाया जाएगा।

राजस्थान में जैव विविधता रजिस्टर

राजस्थान में शीघ्र ही प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जनता जैव विविधता रजिस्टर (People's Biodiversity Register, PBR) होगा। यह हमारी जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान को जानने, उपयोग करने और सुरक्षित रखने के लिए एक परिवर्तनात्मक दृष्टिकोण है, जो जैव विविधता संसाधनों और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय विशिष्ट जानकारीयों को एक साथ संरक्षित करते हैं। इस जैव विविधता रजिस्टर से राज्य के जैव विविधता और पारंपरिक दवाओं के ज्ञान के संरक्षण में मदद मिलेगी।

जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अनुसार ग्रामपंचायत स्तर पर एक जैव विविधता प्रबंध समिति का गठन किया जायेगा। जो जैव विविधता रजिस्टर तैयार करेगी। हालांकि 2016 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) में एक मामला दर्ज होने तक इसे कर्मचारियों की जटिलता और कमी के कारण लागू नहीं किया गया था। केस चंद्रपाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2016, के पश्चात् National Green Tribunal,NGT ने सभी राज्यों को इसे गंभीरता से लेने और रजिस्टर तैयार करने का आदेश दिया।

इससे राज्य में जैव संसाधनों के अधिक दोहन पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी। राजस्थान में, लगभग 10,000 ग्राम पंचायतें और समितियाँ हैं। राज्य में प्रति पंचायत एक रजिस्टर तैयार करने के लिए के लिए कम

से कम 50,000 से 1 लाख रूपए यानी 100 करोड़ रूपए की आवश्यकता है। इस रजिस्टर को तैयार करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्राप्त करने के लिए, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के साथ संपर्क किया है।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIN) अधिसूचना, 2020

दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्यावरण कार्यकर्ता विकांत तोंगड़ की याचिका पर कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए विवादित पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIN) अधिसूचना, 2020 पर जनता द्वारा टिप्पणी भेजने की समयसीमा को बढ़ाकर 11 अगस्त कर दिया। इससे पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने समयसीमा 30 जून 2020 तय की थी।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा(1972) पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने जल नियंत्रण (1974) और वायु प्रदूषण (1981) के संबंध में जल्द ही कानून बना दिया था लेकिन वर्ष 1984 में भोपाल गैस रिसाव आपदा के बाद ही देश में 1986 में पर्यावरण संरक्षण के लिये एक कानून बनाया गया। इसी कानून के तहत साल 1994 में पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों को अधिसूचित किया गया। जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, उपभोग और प्रदूषण को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिये एक कानूनी तंत्र स्थापित करता है। हर विकास परियोजना को पहले पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिये EIA प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।और सभी शर्तों का पालन किए जाने पर ही परियोजनाओं को कार्य शुरू करने की मंजूरी दी जाती है ईआईए के महत्वपूर्ण पहलू हैं:

- जोखिम आकलन,
- पर्यावरण प्रबंधन और
- अंतिम उत्पाद की निगरानी।

1994, EIA अधिसूचना में वर्ष 2006 में संशोधन किया गया था।

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIN) अधिसूचना, 2020

इस वर्ष की शुरुआत में सरकार ने वर्ष 2006 से जारी संशोधनों और प्रासंगिक न्यायालय के आदेशों को शामिल करने और EIA की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और तेज़ बनाने के लिये इसे फिर से तैयार किया है। वर्ष 2020 का मसौदा ईआईए प्रक्रिया पर्यावरण की सुरक्षा में सार्वजनिक सहभागिता को सीमित करते हुए सरकार की विवेकाधीन शक्ति का बढ़ाया जाना प्रस्तावित करता है। राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित परियोजनाओं को स्वाभाविक रूप से रणनीतिक माना जाता है, सरकार अन्य परियोजनाओं के "रणनीतिक" टैग पर विचार करती है। 2020 के मसौदे में "ऐसी परियोजनाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाने" जैसी कोई जानकारी नहीं है। यह

वैसे किसी भी रणनीतिक योग्य समझे जाने वाले परियोजनाओ के अविलंबित क्लियरेंस के लिये एक रास्ता खोल देता है, बिना किसी स्पष्टीकरण के।
ईआईए अधिसूचना, 2020 ने एक सबसे चिंताजनक और पर्यावरण विरोधी प्रावधान ये शामिल किया गया है कि अब उन कंपनियों या उद्योगों को भी क्लीयरेंस प्राप्त करने का मौका दिया जाएगा जो इससे पहले पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करती आ रही हैं. इसे 'पोस्ट-फैक्टो प्रोजेक्ट क्लीयरेंस' कहते हैं।

विश्व पर्यावरण दिवस 2020

हर साल 5 जून को विश्व स्तर पर विश्व पर्यावरण दिवस(World Environment Day) मनाया जाता है। यह दिन पर्यावरण संक्षरण और लोगों को प्रकृति के महत्त्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। प्रतिवर्ष अलग अलग देश विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी करते है। इस वर्ष के मेजबान जर्मनी व कोलंबिया है।

विश्व पर्यावरण दिवस, 2020 थीम

विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम "जैव विविधता" ("Biodiversity") है। इस थीम के जरिए इस बार संदेश दिया जा रहा है कि जैव विविधता संरक्षण एवं प्राकृतिक संतुलन होना मानव जीवन के अस्तित्व के लिए बेहद आवश्यक है। जैव विविधता जमीन पर और पानी के नीचे सभी जीवन का समर्थन करती है।

विद्युत मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 पर #iCommit पहल शुरू की

केन्द्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर.के.सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 'आईकोमिट #iCommit' अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़ कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली कायम करने के लिए आह्वान है। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (EESL) द्वारा शुरू की गई '#आईकोमिट' पहल से सरकारों, कंपनियों तथा बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय संगठनों, थिंक टैंक एवं व्यक्तियों आदि को एकजुट कर साथ लाया जा रहा है।
यह पहल भारत सरकार के प्रमुख उपक्रमों को भी साथ लाएगी और बढ़ावा देगी जैसे:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020,
- FAME 1 और 2,
- दीनदयालउपध्याय ग्राम ज्योति योजना,
- सौभाग्य योजना,
- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (UDAY),
- अटल वितरण प्रणाली में सुधार योजना (AJAY),

- स्मार्ट मीटर राष्ट्रीय कार्यक्रम,
- प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम),
- सोलर पार्क, ग्रिड कनेक्टेड छत,
- उजाला (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All-UJALA)
- अटल ज्योति योजना (AJAY) आदि।

लैंटाना झाड़ी सज्जनगढ़ अभयारण्य के लिए खतरा

उदयपुर के सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में लैंटाना झाड़ी की विषाक्त प्रजाति तेजी से फ़ैल रही है। 519.6 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले अभयारण्य में लगभग 200 हेक्टेयर के क्षेत्र में खरपतवार तेजी से फैल रही है।

लैंटाना खरपतवार

लेंटाना एक बहुत ही खतरनाक एवं विषाक्त बहुवर्षीय झाड़ीनुमा पौधा है। यह निचली जमीन से लेकर 1600 मीटर की ऊँचाई वाली पहाड़ियों में पाया जाता है। यह सूखा सहन करने की अत्यधिक क्षमता रखता है। पौधे के रासयनिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसकी पत्तियों एवं फलों में 'लेंटाडेन' एवं 'लेनकैमेंरेन' नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। जिसके कारण मवेशी, भेड़, घोड़े, कुत्ते, गिनी सूअरों और खरगोशों द्वारा इसकी पत्तियाँ व फल खाने पर उनमें अनेक प्रकार की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, इसके अतिरिक्त यह कीटों एवं रोगों के विषाणुओं को भी आश्रय देता है जिसके कारण जंगलों में उपयोगी वृक्षों पर रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है।

विभाग द्वारा कार्यवाही

वन विभाग ने बारिश में होने वाली लैंटाना खरपतवार की अनियंत्रित वृद्धि को रोकने के लिए बीज बनाने और बारिश में बह जाने से पहले झाड़ियों को हटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है।

सरकारी परियोजनायें

सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना का लाभ

28 जनवरी 2020 को राजस्थान सरकार ने सिलिकोसिस पीड़ितों की संतानों को पालनहार योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस सन्दर्भ में वित्त विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। योजना के अनुसार परिवार में माता अथवा पिता के सिलिकोसिस से पीड़ित होने की स्थिति में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना के लाभ देय होंगे। इसके लिए पालनहार योजना की पात्रता सूची में सिलिकोसिस पीडित परिवार की श्रेणी को जोड़ा जायेगा। इस निर्णय से प्रदेशभर में सिलिकोसिस पीड़ित परिवारों के करीब 15,828 बच्चो को लाभ मिलेगा।

पालनहार योजना

08.02.2005 से लागू इस योजना में अनाथ बच्चो के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत ना करके समाज के भीतर ही बालक-बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्ति को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। यह योजना आरम्भ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चो हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय-समय पर संशोधन कर निम्नांकित श्रेणियों को जोडा गया है:-

- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता की संतान
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता व नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- एड्स पीडित माता/पिता की संतान
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता की संतान
- विकलांग माता/पिता की संतान
- तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला की संतान

पालनहार योजना के अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिकआय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। पालनहार योजना में से 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 500 रुपये तथा 6-18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रति माह 1000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान है।

नवजात सुरक्षा योजना

9 फरवरी 2020 को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा जी ने नवजात सुरक्षा योजना (Navjaat Suraksha Scheme) की घोषणा की है। योजना को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने इसे सरकार की निरोगी योजना के भीतर शामिल किया है।नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राज्य के कम वजन वाले , कुपोषित और समय से पूर्व जन्म लेने वाले नवजात शिशुओं को राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा लाभ प्रदान किये जायेंगे। साथ ही परिजनो को कंगारू मदर केयर तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा व समय-समय पर कैंप का आयोजन कर आम जन को स्वास्थ्य हेतु जागरूक भी किया जाएगा।

कंगारू मदर केयर तकनीक

कंगारू मदर केयर तकनीक के अंतर्गत माँ नवजात को अधिक से अधिक अपने शरीर से चिपका कर रखती है तथा शिशु को स्वस्थ रखने के लिए स्तनपान का विशेष ध्यान रखती है। skin-to-skin contact between mother and baby से मां के शरीर की गर्मी बच्चे के शरीर तक पहुंचती है जिसकी वजह से बच्चा ठंडे बुखार का शिकार होने से बच जाता है।

कंगारू मदर केयर तकनीक के लाभ:

- कंगारू मदर केयर तकनीक को नवजात सुरक्षा योजना में शामिल करने के पीछे का कारण यह है कि इस तकनीक में कोई पैसा खर्च नहीं होता है और शिशु साधारण तरीके से स्वास्थ्य रहता है।
- मदर केयर तकनीक आम जन तक पहुँचाने के लिए 77 ट्रेनर नियुक्त किये जाएंगे जो हर नगर में जा कर स्वास्थ्य केयर के कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग देंगे।
- नवजात सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विभाग ने पहले से चल रही योजना Nirogi राजस्थान अभियान में भी इस तकनीक को शामिल करने का निर्णय लिया है।

पूर्वी नहर परियोजना/ ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट

- पूर्वी नहर परियोजना से राजस्थान के 13 जिले अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के अंतर्गत चम्बल, कुन्नू, कालीसिंध, कुल व पार्वती ये 5 नदियाँ आपस में जुड़ जायेंगी।
- इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 38 हजार करोड़ का है। राजस्थान सरकार इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए प्रयास कर रही है।

सुपोषित माँ अभियान

29 फरवरी, 2020 को लोकसभाअध्यक्ष ओम बिरला तथा केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कोटा-बूंदी क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरूआत की है। इस अभियान के अंतर्गत कुपोषण की शिकार गर्भवती महिलाओं को पूरे 9 माह तक विशेष पोषक आहार उपलब्ध करवाया जायेगा साथ ही प्रति माह मेडीकल चैकअप करवाया जायेगा।

कामधेनु डेयरी योजना

राजस्थान सरकार ने देसी गाय के हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कामधेनु डेयरी योजना शुरू की है। योजना का संचालन पशुपालन विभाग द्वारा किया जाएगा। सरकार राज्य के पशुपालकों और किसानों को डेयरी खोलने के लिए 90% तक लोन देगी। इसमें 30% राज्य सरकार देगी 60% राशि बैंक के द्वारा लोन मिलेगा 10% राशि डेयरी स्थापित करने वाले पशुपालकों, गोपालकों, कृषकों, नव युवकों को देनी होगी। डेयरी योजना तहत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत सब्सिडी भी दी जाएगी। डेयरी स्थापित करने वाले शिक्षित पशुपालक को पशुपालन का अनुभव और खुद की भूमि होना आवश्यक है।

थार योजना

राजस्थान सरकार के अनुसार कृषि क्षेत्र में नये निवेश के लिए ट्रांसफॉर्मिंग एण्ड हारवेस्टिंग एग्रीकल्चर एण्ड अलाइड सेक्टर इन राजस्थान योजना - थार योजना लाई जाएगी। इसके माध्यम से खेती में लागत को कम करना, किसानों की आमदनी में वृद्धि करना, कृषि प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना तथा राज्य के कृषि एवं संबंधित उत्पादों को ब्रांड राजस्थान के तहत देश एवं दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने आदि नवाचार शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री राज नीर योजना

13 मार्च 2020 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने विधानसभा में "मुख्यमंत्री राज नीर योजना" की घोषणा की।

मुख्यमंत्री राज नीर योजना के अंतर्गत

- राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा।
- इसके लिए खराब पड़े वाटर मीटरों को स्मार्ट वाटर मीटरों से बदला जाएगा।

- पहले चरण में एक लाख से -अधिक आबादी वाले 29 शहरों में आगामी 3 वर्षों में 10 लाख वाटर मीटर बदले जाएंगे। इसके लिए वित्त वर्ष 2020-21 में 25 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जा रहा है।
- इसी तरह ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू उपभोक्ताओं को 55 एलपीसीडी निःशुल्क पेयजल आपूर्ति की जाएगी तथा मरूस्थलीय क्षेत्रों में 70 एलपीसीडी तक जल उपभोग माफ रहेगा।

राजस्थान स्वास्थ मित्र चयन

राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य विभाग और रोगियों के मध्य दूरियों को कम करने के उद्देश्य से सहायक नर्स मिडवाइफ्स (ANM), आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मौजूदा बेड़े के अतिरिक्त 80,000 स्वास्थ मित्र तैनात करने का निर्णय लिया है | राजस्थान के प्रत्येक गावं से एक पुरुष व एक महिला को चयनित कर स्वास्थ्य मित्र बनाया जायेगा सभी चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा की आवश्यकता के मामले में लोगों की मदद करने और मार्गदर्शन करने तथा समुदाय के बीच जागरूकता पैदा करने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

राजस्थान स्वास्थ्य मित्रों के निम्न कर्तव्य होंगे -

- लक्षणों व संकेतों के आधार पर बीमारी की प्रकृति को पहचान कर बिना देरी किये उचित चिकित्सा उपचार के लिए मार्गदर्शन करेंगे |
- ब्लड प्रेशर (BP), आहार और जीवनशैली में बदलाव का सुझाव जो बीमारी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो प्रदान करना।
- ब्लड शुगर लेवल की जाँच करना और इसे नियंत्रित करने के लिए उचित आहार और व्यायाम का सुझाव देना |
- इंजेक्शन और IV लाइन प्रदान करना,कटे छिले घाव की ड्रेसिंग और फिजियोथेरेपी |
- निरोगी राजस्थान योजना के तहत बीमारियों के बारे में जागरूकता फैलाना।
- टीकाकरण, संस्थागत प्रसव, पूर्व-प्रसव चेकअप के द्वारा शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृ मृत्यु दर (MMR) को कम करेंगे।
- वेक्टर जनित बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के प्रसार की रोकथाम में सहायता।
- केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए चल रही स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को शिक्षित करना और उनका लाभ दिलाना।

इन्दिरा रसोई योजना

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'कोई भूखा ना सोए' के संकल्प को ध्यान में रखते हुए 20 अगस्त 2020 को 'इन्दिरा रसोई योजना' की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब एंव निर्धन लोगों

को रियायती दर पर दो समय का शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री ने इस योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रूपए खर्च करने का ऐलान किया है। इस योजना के माध्यम से नगर पालिका क्षेत्र में 2 रसोई, नगर परिषद क्षेत्र में 5 रसोई जबकि नगर निगम के क्षेत्र में सबसे अधिक 8 रसोईयों की स्थापना की जाएगी। इससे पूर्व भी राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चलाई जा रही थी।

ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) परियोजना

28 मई, 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की 10 कृषि उपज मंडियों में ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार) परियोजना से संबंधित सभी कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विशिष्ट संस्था के माध्यम से कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इससे इन मंडियों में राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) परियोजना का कार्य बेहतर ढंग से संचालित हो सकेगा। इन 10 मण्डियों को दो क्लस्टर में विभाजित करके ई-उपापन सम्बन्धी कार्यवाही की जाएगी। प्रथम क्लस्टर में कोटा, बारां, रामगंज मण्डी, बून्दी एवं देवली सम्मिलित है तथा दूसरे क्लस्टर में नागौर, बीकानेर, मेड़ता, श्रीगंगानगर एवं जोधपुर अनाज मंडी में सम्पूर्ण व्यवहार-ईनाम पर किया जाना है।

इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट

18 मई, 2020 को मुख्यमंत्री निवास से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय चिकित्सालयों में जन्म लेने वाली नवजात बालिकाओं को नि:शुल्क 'इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट' वितरण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने जयपुर जनाना हॉस्पिटल से आई दो प्रसूताओं सोनम एवं मीनाक्षी की नवजात बालिकाओं को पिंक कलर के किट सौंपे। बच्चे के जन्म होते ही उसे पुराने कपड़ों में लपेटने से होने वाले इंफेक्शन के खतरे को रोकने और नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए राज्य बजट में इसकी घोषणा की गई थी। शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से नवजात बालकों को भी जुलाई, 2020 से नीले रंग का किट वितरित किया जाएगा।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009

15 मई, 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE) के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश में आय सीमा 1लाख प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2.5 लाख प्रतिवर्ष कर दी है। RTE अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों की 25% सीटों पर कमजोर आय वर्ग वाले लोगों के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जाता है। अभी तक एक लाख वार्षिक आय सीमा वाले लोग ही इन सीटों के लिए आवेदन कर पाते थे किन्तु अब 2.5 लाख वार्षिक आय सीमा के लोग भी आवेदन कर सकेंगे।

भारत माला प्रोजेक्ट,रिफाइनरी सेतु सड़क

पंजाब के भटिंडा, राजस्थान के पचपदरा और गुजरात के जामनगर में स्थित रिफाइनरी को जोड़ने के लिए राजस्थान में 6 लेन ग्रीनलाइव हाइवे का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। बाडमेर जिले के आसोतरा तक की कार्य प्रक्रिया प्रारम्भ होने के साथ ही अब आसोतरा से जामनगर,गुजरात तक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। 25-25 किलोमीटर के कार्य अलग-अलग चरणों में करवाए जा रहे है। 1316 किमी की यह सडक जिसकी लागत करीब 5379 करोड़ है को तीनों ही प्रदेश अपनी आर्थिक सड़क के रूप में देख रहे है। भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बन रहे हाईवे का तीनों राज्यों को लाभ मिलेगा।
इस रोड की विशेषता यह होगी की इसके दोनों ओर दीवार होगी। जिससे जानवर या अन्य अवरोधक नहीं आ पाएंगे और सड़क पर वाहन रफ्तार से दौड़ेंगे इस सड़क में गतिअवरोधक भी नहीं होंगे। यह सड़क फिलहाल 6 लेन बनाई जा रही है किन्तु इसको 8 और 10 लेन में विस्तारित करने के लिए जमीन की आवाप्ति पहले से की जा रही है।

SMILE (Social Media Interface for Learning Engagement)

- राजस्थान सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से हुए Lockdown के कारण 13 अप्रैल, 2020 से Project SMILE (Social Media Interface for Learning Engagement) का शुभारम्भ किया।
- इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सभी पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारीयों (panchayat elementary education officer, PEEO) ने अपने समस्त शैक्षिक स्टाफ से समन्वय कर सभी कक्षाओं के Whatsapp ग्रुप बनाये है। इन वाट्सएप ग्रुप पर रोजाना प्रात: 9 बजे से पहले शैक्षिक सामग्री के कक्षावार यू-ट्यूब लिंक जारी किए जाते है जिनसे छात्र/छात्राएँ निरंतर अध्ययन कर सके और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो पाए। यह कार्यक्रम 13 अप्रैल से प्रतिदिन प्रात: 9 बजे टाइम टेबल से शुरू किया जाता है। इस बार ग्रीष्म अवकाश के दौरान भी बच्चे निरंतर इन वीडियोज के द्वारा शिक्षा से जुड़े रहे। साथ ही

शैक्षिक सामग्री के विषय में विषयाध्यापक व अभिभावकों से ऑनलाईन Feedback form भी भरवाए गए है।

- **शिक्षावाणी कार्यक्रमः** 11 मई, 2020 से रोज प्रातः 11 बजे से 11.55 तक प्रसार भारती ने 25 आकाशवाणी केन्द्रों से शिक्षावाणी कार्यक्रम का नि:शुल्क प्रसारण किया है। इससे प्रदेश के विद्यार्थी रेडियो पर भी पढ़ाई कर सकेंगे। आकाशवाणी की अलग-अलग शहरों की अलग-अलग frequency होती है। यह कार्यक्रम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम 11 मई से शुरू होकर 30 जून तक चलाया गया।
- **शिक्षा दर्शन :** 1 जून, 2020 से प्रदेश के स्कूली बच्चे दूरदर्शन (डीडी राजस्थान) से भी पढ़ाई कर रहे हैं। रेडियो की तरह अब टीवी पर भी प्रतिदिन 195 मिनिट (3.15 घण्टे) का शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए 2 घंटे और पहली से 8वीं कक्षा के लिए 75 मिनिट का शैक्षिक प्रसारण हो रहा है।
- प्रदेश में लॉकडाउन की वजह से इस बार स्कूली वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाया है। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 11 के नियमित विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं में क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये है। कक्षा 9 व 11वीं के लिए अंकों का प्रतिशत अर्द्धवार्षिक व अन्य परीक्षाओं के प्राप्तांकों के आधार पर निकाला गया है। ये आदेश केवल शैक्षिक सत्र 2019-20 के लिए ही मान्य है।

22 मई 2020 को राज्य सरकार ने प्रदेश के 76 ब्लॉक्स में अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए है। सरकार ने 2020-21 के बजट में 167 ब्लॉक्स में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की थी,ये नये 167 स्कूल महात्मा गाँधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल के नाम से खोले जायेंगे।

राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 लागू

कोविड-19 जैसी संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 को लागू किया है। इसमें महामारी से निपटने के लिए जहाँ सरकार को अधिक अधिकार मिले हैं, वही बीमारी को फैलाने वालों के खिलाफ अब और सख्त कार्रवाई होगी। कानून के उल्लंघन पर 10 हजार तक का जुर्माना, दो साल की सजा या दोनों सजा एकसाथ हो सकती है। अब तक महामारी से निपटने के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (NDMA) के अनुसार कार्रवाई की जा रही थी किन्तु अब पुलिस स्वप्रेरणा से अपराध दर्ज कर सकती है।

नए कानून के प्रावधान: राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 की धारा 4 की उपधारा 2 के अनुसार किसी भी प्रथा या कृत्य के तहत भीड़ एकत्र होने से रोकने, व्यक्ति को क्वॉरंटीन करने, क्वॉरंटीन सेंटर बनाने, निरीक्षण, राज्य की सीमाओं को सील करने, लोक परिवहन के वाहनों को नियमित करने, सामाजिक दूरी बनाने, धार्मिक एवं सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्र करने से रोकने, सरकारी एवं निजी कार्यस्थल पर काम करने वालों को

प्रतिबंधित करने, दुकानों एवं व्यावसायिक कार्यालयों को खोलने व बंद करने, आवश्यक सेवाओं में मीडिया व स्वास्थ्य सहित अन्य को लेकर इसमें कार्रवाई की जा सकती है।

नए प्रावधान एवं दोषी पाए जाने पर जुर्माना:

- बिना मास्क ग्राहक को सामान बेचने पर दुकानदार को जुर्माना चुकाना होगा: 500 रु.
- सार्वजनिक स्थान, कार्यस्थल पर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना चुकाना होगा: 200 रु.
- सार्वजनिक स्थान पर पान-तंबाकू-गुटखा खाने व थूकने पर जुर्माना चुकाना होगा: 200 रु.
- सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने पर जुर्माना चुकाना होगा: 500 रु.
- शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचते समय सोशल डिस्टेसिंग का पालन नहीं होने पर जुर्माना चुकाना होगा: 500 रु.
- सार्वजनिक स्थल पर 6 फीट की उचित दूरी नहीं रखने पर जुर्माना चुकाना होगा: 100 रु.
- बिना अनुमति विवाह समारोह या अन्य भीड़ वाले कार्यक्रमों का आयोजन करने पर जुर्माना चुकाना होगा: 5000 रु.

सरकारी कार्मिकों को क्वॉरंटीन अवकाश मिलेगा

कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है की सरकारी कर्मचारियों को कोविड-19 के संक्रमण पर भी क्वॉरंटीन अवकाश मिलेगा। अवकाश उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जो चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा क्वॉरंटीन किए जाएंगे। तीन वर्ष का नवाभ्यास काल पूरा ना करने वाले कर्मचारियों का अवकाश भी स्वीकृत किया जायेगा। क्वॉरंटीन अवकाश के लिए संबंधित जिले का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल की सिफारिश जरूरी होगी। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को कालरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, डिप्थिरिया, टायफस बुखार, सेरेब्रोस्पाइनल मेनिंजाइटिस और स्वाइन फ्लू में क्वॉरंटीन अवकाश का प्रावधान है।

फ्लैगशिप योजनाएँ

राज्य सरकार ने समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के सशक्तिकरण और उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से अपनी 19 योजनाओं को फ्लैगशिप योजनाओं के रूप में घोषित किया है। सरकार ने राज्य की प्राथमिकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार, समाज के कमजोर समूहों इत्यादि को मद्देनजर रखते हुए 16 मई, 2020 को फ्लैगशिप योजनाओं की घोषणा की है।

19 फ्लैगशिप योजनाएँ

आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि फ्लैगशिप योजनाओं में शद्ध के लिए यद्ध, निरोगी राजस्थान, मुख्यमत्रा निःशुल्क दवा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना,आयुष्मान भारत महात्मा गाँधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, एक रुपए किलो गेंहू, महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, सिलिकोसिस पॉलिसी 2019 के अन्तर्गत देय लाभ, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना को शामिल किया गया है। इसके साथ ही वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोशन स्कीम, MSME एक्ट-स्व प्रमाणीकरण, राजस्थान इन्वेस्टमेट प्रमोशन स्कीम (RIPS) 2019 जनसूचना पोर्टल एवं जन आधार योजना को भी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल किया है।

कलेक्टर स्तर पर मॉनिटरिंग होगी: फ्लैगशिप योजनाओं का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि विकास व्यापक रूप से फैले ताकि आय और रोजगार के मामले में इसका लाभ समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को पर्याप्त रूप से प्राप्त हो सके।

इन्दिरा गाँधी मातृ पोषण योजना

17 मार्च, 2020 को आयोजित मातृ वन्दना सप्ताह के समापन समारोह पर राजस्थान के चार जिलों उदयपुर, डूंगरपुर, बाँसवाड़ा तथा प्रतापगढ़ में महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर राज्य सरकार द्वारा 6 हजार रु. की राशि दिए जाने की घोषणा की है। सरकार की इस पहल इंदिरा गाँधी मातृ पोषण योजना के तहत पाँच साल में 375000 हजार लाभार्थियों पर 225 करोड़ रु.खर्च होंगे। यह राशि माता के खाते में अलग-अलग चरणों में निर्धारित शर्ते पूरी करने पर पहुंचाई जाएगी। नई महिला नीति के अनुसार प्रदेश स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इन जिलों में पोषण संकेतक राजस्थान के औसत की तुलना में कम होने के कारण उन पर विशेष ध्यान देने के लिए इनका चयन किया है।

वन नेशन-वन राशन कार्ड

1 जनवरी, 2020 से केन्द्रीय उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा 12 राज्यों राजस्थान, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा, त्रिपुरा, केरल व आन्ध्र प्रदेश में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी गई है। इन राज्यों के राशन कार्डधारी अब इनमे से किसी भी राज्य की राशन की दुकान से राशन खरीद पाएंगे। इसे राशन कार्ड पोटेबिलिटी भी कहते है। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान का निवासी था तो हरियाणा में रहने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है वह पुराने राशन कार्ड से ही हरियाणा की किसी भी सरकारी राशन की दुकान से राशन खरीद सकेगा। उपभोक्ता मंत्रालय ने इस योजना को पूरे देश में लागू करने के

लिए इसी वर्ष जून तक का लक्ष्य रखा है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अगस्त में महाराष्ट्र व गुजरात और आन्ध्र प्रदेश व तेलंगाना के मध्य इस योजना को शुरू किया गया था।

DMIC की कमान RIICO को सौंपी

राज्य सरकार ने DMIC को समाप्त कर 7 मार्च, 2020 को राज्य विधानसभा में दिल्ली-मुंबई इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर (DMIC) का पूरा कामकाज RIICO (रीको) को देने की घोषणा की है। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान निम्न घोषणाएँ की है-

- अगले एक वर्ष में रीको के जरिए प्रथम चरण का भूमि अधिग्रहण पूरा किया जाएगा। मीणा ने जोधपुर में नया हैडीक्राफ्ट निदेशालय खोलने की घोषणा की है। केन्द्र और राज्य की साझेदारी से कार्यरत सांभर सॉल्ट को अपने अधीन लेने के लिए सरकार जल्द कार्यवाही करेगी। केन्द्र ने बिना वित्तीय देनदारी के इस कंपनी को राज्य को देने का प्रस्ताव दिया है।
- जयपर में बीटू बायपास स्थित रीको की 40 हैक्टेयर भमि पर नया 'फिन-टेक पार्क का निर्माण किया जाएगा। यहाँ बड़े बैंकों व IT क्षेत्र की कंपनियों को एक ही स्थान पर निवेश की सुविधा दी जाएगी।
- पूँजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 में लाभान्वित इकाइयों को अनुदान वसूली से छूट
- रीको भूखण्डों की आधारीय दरों में औसतन 25% तक कमी।
- औद्योगिक क्षेत्रों के लिए कलक्टर भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव देंगे।
- रीको भूखण्ड खरीद के लिए एक करोड़ तक का ऋण देगा।
- हस्तशिल्प एपोरियम, इनलेण्ड कंटेनर डिपो का आधुनिकीकरण।

राज्य में पशुओं की डिजिटल टैगिंग

सरकार द्वारा पशुओं का डाटाबेस तैयार करने के उद्देश्य से पशुओं में डिजिटल टैगिंग की योजना लागू की गई है। इस योजना में दुधारू पशुओं में टेगिंग कर पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत, विभाग के कार्यकर्ता पशुपालकों के घर-घर जाकर पशुओं का पंजीकरण कर कान पर टैग लगाएंगे तथा आवश्यक जानकारी जैसे नस्ल, पिछले रोग, दूध की मात्रा, टीकाकरण और मूल्य आदि एकत्र करेंगे। समस्त पंजीकृत पशुओं एवं पशुपालकों की सम्पूर्ण जानकारी ईनाफ साफ्टवेयर में संचित की जाएगी। इस डेटाबेस के संग्रह से स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर पशुओं के क्रय-विक्रय में उचित मूल्य हेतु ई-मार्केट ईनाफ पोर्टल(Information Network for Animal Productive and Health) का विकास किया जायेगा जो की पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने में लाभकारी होगा

योजना के लाभ:

- पशुओं पर लगे टेग नंबर के माध्यम से पशु की समस्त जानकारी घर बैठे ही प्राप्त की जा सकेगी।
- नस्ल सुधार संबंधित जानकारी के द्वारा उन्नत नस्ल के पशुवंश का संरक्षण एवं संवर्धन किया जायेगा। साथ ही टीकाकरण, कृत्रिम, गर्भधान, नाकारा नस्ल के पशुओं का बधियाकरण का रिकार्ड रखने में आसानी होगी।
- राज्य में पशुओं के संक्रामक रोगों के प्रसार एवं संक्रमण पर अंकुश लगेगा।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, किसान अपने पशुओं को वेबसाइट पर बेच सकेंगे तथा खरीदार वेबसाइट पर लॉग इन कर अपनी पसंद का पशु चुन कर बोली लगा सकते हैं।
- अभी यह योजना जयपुर जिले में शुरू की गई है। इसके बाद राज्य के अन्य क्षेत्र भी इसमें शामिल होंगे।

स्वामित्व योजना

24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना की घोषणा की। Swamitva Yojana 2020 के तहत, ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण करने के बाद स्वामित्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ग्रामीण लोगों को जमीन के मालिक होने के प्रमाणस्वरूप उन्हें स्वामित्व रिकॉर्ड दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सम्पत्ति का रिकॉर्ड तैयार कर उसका मालिकाना हक तय करना है। देश के सभी गाँवों में ड्रोन की मदद से प्रत्येक सम्पत्ति की मैपिंग करके गाँव के लोगों को उस सम्पत्ति के मालिकाना हक के कागज दिए जाएंगे।यह योजना अभी छह राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तराखण्ड में प्रायोगिक तौर पर शुरू की जाएगी।

स्वामित्व योजना के लाभ:

- प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के अंतर्गत संपत्ति नामांकन की प्रक्रिया को सरल बनाना है।
- इस योजना के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा गांव, खेत भूमि का मैपिंग किया जाएगा।
- भूमि के सत्यापन प्रक्रिया मैं तेजी और भूमि भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता मिलेगी।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले किसानों को लोन लेने की सुविधा का भी प्रावधान रखा गया है।
- स्वामित्व योजना से सभी ग्राम समाज के काम ऑनलाइन हो जाएंगे।
- ऑनलाइन होने की वजह से लोग अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन देख सकेंगे।
- ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जमीन का ब्यौरा मुहैया रहेगा।
- ई-पोर्टल लोगों को उनकी जमीन के मालिकाना हक का सर्टिफिकेट भी देगा।

राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम अधिनियम 2016 नियम 2020 अधिसूचित

21 मई 2020 को शहरी विकास और आवास (UDH) विभाग ने राजस्थान लैंड पूलिंग स्कीम 2016 के लिए नियमों और अधिनियमों को अधिसूचित किया है। नए नियमों के अनुसार अन्य प्रावधानों के साथ जमीन मालिक को मुआवजे के रूप में 45% विकसित भूमि वापस करने का प्रस्ताव है। पहले यह 25% था।
नागरिक निकाय सभी आवश्यक बुनियादी ढाँचों जैसे सड़क, पार्क, खुली जगह सहित भूमि का आनुपातिक टुकड़ा जमीन मालिक को देगा। इसके साथ ही राजस्थान भी अन्य राज्यों जैसे पंजाब, महाराष्ट्र गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ इस अधिनियम को लागू करने वाले राज्यों की सूचि में शामिल हो गया।

मुख्यमंत्री ने आवासन मण्डल की 25 परियोजनाओं का शुभारम्भ एवं शिलान्यास किया

22 अगस्त, 2020 को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान आवासन मण्डल की 25 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं शुभारम्भ किया। इन नई परियोजनाओं के शुभारम्भ से लोगों को न केवल छत मिलेगी, बल्कि पार्क, कोचिंग हब, ओपन जिम, ओपन थियेटर, फूड कोर्ट, वॉक-वे जैसी सुविधाएँ भी मिलेंगी।

मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की निम्न 14 आवासीय योजनाओं शुभारम्भ किया:

- वाटिका आवासीय योजना, सांगानेर, जयपुर
- महला आवासीय योजना, अजमेर रोड़, जयपुर
- महात्मा ज्योतिराव फुले आवासीय योजना, नसीराबाद (अजमेर)
- निवाई आवासीय योजना, निवाई (टोंक)
- मुख्यमंत्री राज्य कर्मचारी आवासीय योजना, प्रताप नगर, जयपुर
- वीकएण्ड होम पंजीकरण योजना-2020, नायला, जयपुर
- पटेल नगर विस्तार-भाग-2 आवासीय योजना, भीलवाड़ा
- शाहपुरा आवासीय योजना, भीलवाड़ा
- शास्त्री नगर आवासीय योजना, भीलवाड़ा
- अटल नगर आवासीय योजना, भीण्डर, उदयपुर
- द्वारकापुरी योजना, सविना द्वितीय एवं दक्षिण विस्तार आवासीय योजना-उदयपुर
- महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना, बड़ली, जोधपुर
- मानपुर आवासीय योजना, आबूरोड़ शहर, जिला सिरोही
- खोड़ा गणेश फेज चतुर्थ आवासीय योजना किशनगढ (अजमेर)

मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की निम्न 4 मुख्यमंत्री जन आवास योजनाओं का शुभारम्भ किया:

- मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-3, प्रताप नगर, जयपुर
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-28, प्रताप नगर, जयपुर
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-7 (जी.एच.3), इंदिरा गांधी नगर, जयपुर
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सेक्टर-7 (जी.एच.4), इंदिरा गांधी नगर, जयपुर

मुख्यमंत्री ने राजस्थान आवासन मण्डल की निम्न 7 योजनाओं का किया शिलान्यास

- कोचिंग हब, प्रताप नगर, जयपुर
- सिटी पार्क, मानसरोवर, जयपुर
- महात्मा गांधी सम्बल आवासीय योजना, बड़ली, जोधपुर
- जोधपुर चौपाटी, जोधपुर
- कोटा चौपाटी, कोटा
- सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-3 प्रताप नगर, जयपुर
- सामुदायिक केन्द्र, सेक्टर-26 प्रताप नगर, जयपुर

साथ ही उन्होंने राणा सांगा मार्केट, प्रताप नगर, जयपुर का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर गुणवत्ता नियंत्रण के लिए बनाए गए मोबाइल एप 'आरएचबी सजग' को लांन्च किया और पुस्तिका का विमोचन किया।

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल की स्थापना राज्य की आवासीय समस्या के निराकरण हेतु 24 फरवरी, 1970 को **'राजस्थान आवासन मण्डल एक्ट संख्या-4, वर्ष 1970'** के अन्तर्गत की गई थी। वर्तमान में मण्डल का मुख्यालय जयपुर एवं वृत्त कार्यालय जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा, उदयपुर एवं बीकानेर में स्थित हैं।

PMSVANIDHI

1 जून, 2020 को रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र सरकार ने एक विशेष माइक्रो-क्रेडिट सुविधा "प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधि (PMSVANIDHI)" शुरू की है। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। योजना के तहत 10,000 रु. तक की कार्यशील पूँजी ऋण का लाभ दिया जाएगा जिसे एक वर्ष में चुकाया जा सकता है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में वेंडर, हॉकर, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, ठेली फलवाले आदि सहित 50 लाख से अधिक लोगों को योजना से लाभ प्रदान किया जायेगा |

पीएम स्वनिधि ऐप की विशेषताएं

- सर्वेक्षण के आंकड़ों में विक्रेता की खोज
- आवेदकों का ई-केवाईसी
- ऋण आवेदनों का प्रसंस्करण
- वास्तविक समय में निगरानी

स्वनिधि योजना के लाभार्थी पात्र

- नाई की दुकानें
- जूता गांठने वाले (मोची)
- पान की दूकानें (पनवाड़ी)
- कपड़े धोने की दूकानें (धोबी)
- सब्जियां बेचने वाले
- फल बेचने वाले
- रेडी-टू-ईट स्ट्रीट फूड
- चाय का ठेला या खोखा लगाने वाले
- ब्रेड, पकौड़े व अंडे बेचने वाले
- फेरीवाले जो वस्त्र बेचते हैं
- किताबें/स्टेशनरी लगाने वाले
- कारीगर उत्पाद

लोन देने वाली संस्थाएं:

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
- स्मॉल फाइनेंस बैंक
- सहकारी बैंक
- नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां
- माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और एसएचजी बैंक

प्रधानमंत्री कुसुम योजना

7 जुलाई, 2020 को राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड ने 'प्रधानमंत्री कुसुम योजना कम्पोनेंट-ए' के अन्तर्गत प्रदेश के 623 किसानों को 722 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयन्त्र स्थापित करने हेतु आवंटन पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा स्वयं की अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि पर 0.5-2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयन्त्रों की स्थापना की जा सकती है। इससे किसानों को 25 वर्ष तक नियमित आय प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार की कुसुम योजना में राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है, जिसने किसानों की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा यहाँ देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कुसुम योजना में सर्वाधिक क्षमता के सौर संयन्त्र स्थापित किए जाएँगे।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

26 मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते 26 मार्च, 2020 को केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रु.के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत गरीबों को अगले 3 माह (अप्रैल से जून, 2020) तक प्रतिमाह 5 किग्रा.गेहूँ या चावल और 1 किग्रा. दाल मुफ्त में प्रदान करने की घोषणा की गई थी। इस योजना की अवधि जून, 2020 में समाप्त हो रही थी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 30 जून को इस योजना को आगे नवम्बर तक बढ़ाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत देश के 80 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को नवम्बर महीने तक यानि इन 5 महीनो तक 5 किलो गेहू या 5 किलो चावल मुफ्त में सरकार द्वारा मुहैया कराया जायेगा और इसके साथ ही देश के प्रत्येक गरीब परिवारों को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त में दिया जायेगा। इस योजना के नवम्बर तक विस्तार में 90 हज़ार करोड़ रूपये से ज्यादा खर्च होंगे।

कोविड-19 लॉकडाउनः राहत उपाय

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज

5 मई 2020 तक हुई प्रगति के मुख्य बिंदु

कुल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

पैकेज के तहत 39 करोड़ से भी अधिक गरीब लोगों को **34,800 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता मिली

- **पीएम-किसान की पहली किस्त**
  कुल 8.19 करोड़ किसानों को **16,394 करोड़ रुपये** हस्तांतरित किए गए
- दो किस्तों में कुल 25.62 करोड़ महिला जन धन खाताधारकों को **12,810 करोड़ रुपये** दिए गए
- लगभग 2.82 करोड़ वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को **1,405 करोड़ रुपये** दिए गए
- 2.20 करोड़ भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों को **3,493 करोड़ रुपये** की वित्तीय सहायता मिली
- ईपीएफ में अंशदान के रूप में **698 करोड रुपये** हस्तांतरित किए गए, 44.97 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना

- अप्रैल महीने के लिए 36 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा **67.65 लाख टन** अनाज का उठाव किया गया
- अप्रैल के लिए 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **60.33 करोड़** लाभार्थियों को **30.16 लाख टन** खाद्यान्न वितरित किया गया
- मई में अब तक 22 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा **12.39 करोड़** लाभार्थियों को **6.19 लाख टन** खाद्यान्न वितरित किया गया
- **2.42 लाख टन** दालें विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भेजी गई

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

- **4.82 करोड़** मुफ्त गैस सिलेंडर वितरित किए गए

मनरेगा

- 1 अप्रैल 2020 से बढ़ी हुई दरों को अधिसूचित किया गया
- मौजूदा वित्त वर्ष में **5.97 करोड़** व्यक्ति कार्य–दिवस के अवसर पैदा हुए
- राज्यों को वेतन और सामग्री दोनों के लंबित बकाये का भुगतान करने के लिए **21,032 करोड़ रुपये** जारी किए गए
- न्यू इंडिया एश्योरेंस द्वारा शुरु की गई बीमा योजना के तहत सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में काम करने वाले **22.12 लाख** स्वास्थ्य कर्मचारियों को शामिल गया

स्रोतः
वित्त मंत्रालय

/PIB_India /PIBHindi /pibindia /pibindia /pibindia.wordpress.com /pibindia pib.gov.in KBK

डिजाइन कॉन्क्लेव-2020 का शुभारम्भ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 20 अगस्त, 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी के 76वें जन्मदिवस के अवसर पर 'सद्भावना दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'डिजाइन कॉन्क्ले व-2020' कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।

मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में दोनों विभागों (कला, संस्कृति, साहित्य एवं पुरातत्व तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों एवं प्रस्तावित योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वर्चुअल लोकार्पण एवं शुभारंभ किया गया।

लोकार्पण अथवा शुभारंभ किए गए प्रमुख कार्य व योजनाएँ:

- राज्य सरकार की भाषा अकादमियों की ओर से प्रकाशित पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की उपलब्धियों पर आधारित हिन्दी सहित 6 भाषाओं में छपे ई-ब्रोशर
- पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से राजकीय संग्रहालय (बारा) में 5 दीघाएँ
- श्रीगंगानगर जिले में गुरु श्री गोविन्द सिंह पैनोरमा (बूढ़ा जोहड़)
- राजसमन्द जिले में महाराणा कुम्भा पैनोरमा (माकल्यावास)
- भीलवाड़ा जिले में श्री देवनारायण पैनोरमा (मालासेरी-आसीद)
- चित्तौड़गढ़ जिले में परशुरामजी पैनोरमा (मातृकुण्डिया-राशमी)
- चित्तौड़गढ़ में वीर गौरा बादल पैनोरमा
- डीएसटी-आईएएससी उल्कापिण्ड खोज अभियान के लिए प्रतियोगिता
- जॉय का कपः जवाहर कला केन्द्र में कलाकारों के लिए विशेष योजना
- तीन दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का लाइव डेमो
- इंस्टॉलेशन डिजाइन प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन
- अल्बर्ट हॉल में पब्लिक इंस्टॉलेशन पोस्टर का विमोचन तथा मास्क का लोकार्पण
- विभिन्न प्रतियोगिताओं में डिजाइन किये गये मास्क, लिफाफे और फाइल कवर आदि का लोकार्पण

सामान्य करंट अफेयर्स

No Vehicle Day

परिवहन एवं सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्य में सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और वाहनजनित प्रदूषण की की ओर आमजन का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रदेशभर के परिवहन कार्यालयों में 1 जनवरी 2020 से No Vehicle Day की पहल की है। इस पहल के अनुसार महीने का पहला दिन नो व्हीकल डे होगा। मंत्री के आदेशानुसार नो व्हीकल डे को विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी गाड़ी घर पर छोड़कर पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग कर अपने कार्यालय पहुंचेंगे। इसमें परिवहन उडनदस्तों में कार्यरत कार्मिकों, दिव्यांगों, असाध्य रोगों से पीडित एवम अन्य किसी कारण से अक्षम कार्मिकों के लिए छूट प्रदान की गई है।

No Bag Days

राज्य के बजट भाषण 2020 में, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्कूली बच्चों पर शिक्षा का दबाव कम करने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में शनिवार 'नो बैग डे' का प्रस्ताव दिया है। शनिवार को किसी तरह का अध्यापन कार्य नहीं होगा। इस दिन अभिभावक - अध्यापक मीटिंग के अलावा साहित्यिक, एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, स्काऊट, जीवनमूल्य बालसभायें एवं अन्य क्रियायें आयोजित की जाएंगी।

सामाजिक न्याय विभाग पोर्टल का (CCTNS) के साथ एकीकरण

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department) पुलिस विभाग के अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क (CCTNS, Crime and Criminal Tracking Network and Systems) के साथ अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों की वित्तीय सहायता के लिए अपने वेब पोर्टल को एकीकृत करेगा।

- राजस्थान का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्य में समाज के कमजोर और उपेक्षित वर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है।

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार की नई पहल

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जनवरी 2020 में कॉलेज शिक्षा द्वारा 'शिक्षा संकुल' में आयोजित युवा सम्मेलन में विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की।

- **कॉलेज शिक्षा में नई पहल (NICE) कार्यक्रम** - राजस्थान में कॉलेज शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता के लिए 2020 में नई पहल शुरू करने के लिए
- **कमिश्नर की क्लास** - सरकारी कॉलेजों में विशेष क्लास शुरू की जाएगी, जिसके तहत शिक्षा आयुक्त छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए कक्षाएं लेंगे।
- **गर्ल्स एम्पावरमेंट एंड मेंटरिंग (GEM) प्रोग्राम** - कॉलेजों में लड़कियों की बेहतर सुरक्षा और समग्र विकास, विशेष रूप से स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित होगा। इसके लिए महिला शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो आगे लड़कियों को शिक्षित करेंगी।
- **राजस्थान स्वस्थ युवा और नैतिक शिक्षा (RHYME) कार्यक्रम** - छात्रों के बीच स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में जागरूक फ़ैलाने और उन्हें नैतिक मूल्यों के साथ शिक्षित करने के लिए
- **प्रशासनिक प्रवीणता और प्रोग्रेसिव लर्निंग एफर्ट (APPLE) की घोषणा** - छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रशासनिक दक्षता और प्रगतिशील शिक्षण प्रयास कार्यक्रम, इसमें प्रधानाचार्यों और वरिष्ठ संकाय सदस्यों का प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल होगा।
- **अर्जुन दीक्षा कार्यक्रम** - खेलों में रुचि रखने वाले छात्रों को बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए "अर्जुन दीक्षा कार्यक्रम"के तहत विभिन्न अंतर-राज्य खेल और खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे।
- **प्राइवेट कॉलेजों में मुफ्त कोचिंग** - सरकारी कॉलेजों में 'प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम' के नक्शेकदम पर चलते हुए, निजी कॉलेजों में भी इसी तरह की कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जो छात्रों को मुफ्त में उपलब्ध होंगी।

राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग को CBIP द्वारा सम्मानित

19 फरवरी, 2020 को राजस्थान सरकार के जल संसाधन विभाग को नई दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड (Central Board of Irrigation & Power, CBIP) द्वारा सम्मानित किया गया।केंद्र सरकार के केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड द्वारा 10 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किये गए, जिसमें राजस्थान ने दो श्रेणियों में पुरस्कार प्राप्त किये इंदिरा गांधी नहर परियोजना में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में उत्कृष्टता(Integrated Water Resources Management) और किसानों के सिंचाई प्रबंधन में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रभावी सिंचाई प्रबंधन(Participatory approach of irrigation water management)। दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया और केंद्रीय जल आयोग के अध्यक्ष आरके जैन ने विभाग के सचिव नवीन महाजन को CBIP अवार्ड-2020 प्रदान किया।

इससे पूर्व भी केंद्र सरकार ने राज्य के जल संरक्षण व सिंचाई जल के दक्षतापूर्ण उपयोग के प्रयासों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया था। प्रदेश की नर्मदा नहर परियोजना को जल संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए

प्रथम पुरस्कार तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना द्वितीय चरण के अंतर्गत तेजपुर नहर प्रणाली को भी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति अपनाकर जल के दक्षतापूर्ण उपयोग पर द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

मेवाड़ के चार धाम:

राजसमंद सांसद दीया कुमारी ने केंद्र से आग्रह किया कि वह मेवाड़ के चार धाम के रूप में एकलिंग जी (उदयपुर), श्रीनाथजी नाथद्वारा (राजसमन्द), श्रीद्वारकाधीशजी कांकरोली (राजसमन्द) और श्री चारभुजा जी (राजसमन्द) को सम्मिलित करते हुए एक आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर विचार करें।

चिड़ी बल्ला

28 अप्रैल, 2020 को राजस्थान में बनी फिल्म 'चिड़ी बल्ला' ने अमरीका के प्रतिष्ठित ग्लोबल म्यूजिक अवॉर्ड्स में सिल्वर अवॉर्ड जीता है। निर्णायक जूरी ने फिल्म को इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल म्यूजिक और बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के लिए पुरस्कृत किया है। फिल्म को 38 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।

- फिल्म के डायरेक्टर - राधेश्याम पीपलवा

मुक्ति कारवां रथ

राजस्थान में बाल मजदूरी, बाल दुर्व्यवहार तथा बाल शोषण के खिलाफ जनचेतना का संदेश देने के लिए राजस्थान पुलिस एवं कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में पुलिस महानिदेशक डॉ. भूपेन्द्र सिंह ने मुक्ति कारवां संदेश यात्रा को अल्बर्ट हॉल पर एक समारोह के दौरान हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया था। समारोह में डीजीपी भूपेन्द्र सिंह ने आओ बनाये बालमित्र राजस्थान का शुभारम्भ किया। बचपन बचाओ आंदोलन, बाल आश्रम, श्री आसरा विकास संस्थान व गायत्री सेवा संस्थान ने भी इस अभियान में सहयोग किया। मुक्ति कारवां ने प्रदेशभर का दौर कर बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया।

राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2020

इस नीति में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को लचीला बनाना, निजी भूमि रीको द्वारा निवेश तथा रीको की भूमि-निजी निवेश मॉडल पर PPP मोड पर औद्योगिक पार्कों का विकास करना
प्लग एण्ड प्ले सुविधाओं एवं बहुमंजिला कारखानों को बढ़ावा देना।
पिछड़े क्षेत्र में उद्योग स्थापना हेतु रियायती दर पर बंजर भूमि आवंटन।
पेट्रो केमिकल उद्योग के लिए तेल रिफाइनरी के पास औद्योगिक टाऊनशिप विकसित करना।
थ्रस्ट सेक्टर एवं पिछड़े व अति पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना।
एंकर इकाइयों को आकर्षक प्रोत्साहन एवं स्टार्टअप हेतु नई स्टार्टअप नीति का निर्माण करना।

MSME को गुणवत्ता प्रमाणन, रिसर्च एण्ड डवलपमेंट आदि के लिए सहायता प्रदान करना।
अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, कुटीर उद्योगों, फुटकर व्यापारियों एवं स्वयं सहायता समह के उद्यमियों के लिए विशेष योजना का प्रावधान किया गया है।

मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन

सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन की टक्कर से मृत्यु होने पर अब 12 लाख एवं गम्भीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रूपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 161 में संशोधन किया गया है।
अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु अथवा गम्भीर घायल होने पर प्रभावित को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 163 एवं 161 के अन्तर्गत 'तोषण निधि स्कीम' के तहत सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर इस स्कीम के अंतर्गत 25 हजार एवं गम्भीर घायल होने पर 12,500 रूपये की सहायता राशि देने का प्रावधान था।

राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 5 मार्च 2020 को राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल की गवर्निंग काउन्सिल की बैठक में जयपुर के सांगानेर में बंद पड़े फ्लाइंग स्कूल को पुनः प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि पीपीपी मोड पर इस स्कूल को संचालित करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में 19 एयर स्ट्रिप के रूप में बड़ा आधारभूत ढांचा उपलब्ध है। इन हवाई पट्टियों का सुदृढीकरण करते हुए इनका पूरा उपयोग इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने में किया जाए।मुख्यमंत्री ने राज्य में एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम 'उडान' के तहत विभिन्न एयरलाइंस को आमंत्रित कर राज्य के महत्वपूर्ण शहरों से हवाई सम्पर्क सेवा शुरू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से संचालित इन्ट्रा स्टेट हवाई सेवाओं को पुनः चालू करने की संभावनाएं तलाशी जाएं। इससे पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC-ST आरक्षण 10 साल बढ़ा

25 जनवरी, 2020 को संविधान संशोधन (126वां) बिल लोकसभा में पास किया गया। बिल में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के आरक्षण को 10 साल तक बढ़ाने का प्रावधान है।इस प्रावधान को आगे बढ़ाने के लिए विधानसभाओं की ओर से भी पास किया जाना अनिवार्य है। संसद और राज्य विधानसभाओं में संविधान के अनुच्छेद-334 के तहत SC-ST के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। 25 जनवरी से यह संशोधन प्रभावी होगा।

पंचायत पुरस्कार 2020 राजस्थान

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 के अवसर पर, केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता देते हुए पंचायतों को प्रोत्साहन देने हेतु देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया है

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के बारे में संक्षिप्त जानकारी

1992 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया और पंचायती राज संस्थान का कॉन्सेप्ट पेश किया गया। इस कानून की मदद से स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा शक्तियां दी गईं। उनको आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की शक्ति और जिम्मेदारियां दी गईं। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। तब से 24 अप्रैल के दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पहली बार पंचायत राज दिवस 2010 में मनाया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की देखरेख के लिए 27 मई 2004 को पंचायती राज मंत्रालय को एक अलग मंत्रालय बनाया गया

राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020

2020 का राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस झांसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया था और माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय आयोजन का उद्घाटन करने और देश भर के सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थानों को संबोधित करने के लिए अपनी तरह की सहमति दी थी। किन्तु, देश में COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण, 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को डिजिटल रूप से मनाने का निर्णय लिया गया।

पंचायत पुरस्कार 2020

प्रतिवर्ष इस दिन केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सेवाओं और सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण में सुधार के लिए बेहतर कार्यों को मान्यता देते हुए पंचायतों को प्रोत्साहन देने हेतु देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों/ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया जाता है
पुरस्कार निम्न श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं:

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP),
- नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP),
- बाल-अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA),
- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पुरस्कार
- ई-पंचायत पुरस्कार (केवल राज्यों / केंद्र शासित प्रदेश को दिया जाता है)।

इस वर्ष देश में लॉक डाउन की स्थिति होने के कारण केवल प्रारम्भ के तीन क्षेत्रों दीन दयाल उपाध्याय पंचायत शक्तिकरण पुरस्कार (DDUPSP), नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP), बाल-अनुकूल ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA) में ही चुनाव तथा पुरस्कार वितरण किया गया। अन्तिंम दो श्रेणियों में चुनाव COVID स्थिति के सुधरने उपरांत ही किया जायेगा।

पंचायत पुरस्कार 2020: राजस्थान

राजस्थान की निम्न ग्राम पंचायतों ने विभिन्न श्रेणियों के तहत पुरस्कार जीता:

- **ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) पुरस्कार** - जोधपुर जिले के मंडोर ब्लॉक पंचायत में नांदरी ग्राम पंचायत।
- **बाल सुलभ ग्राम पंचायत पुरस्कार (CFGPA)** - टोंक जिले के निवाई ब्लॉक पंचायत में सुनारा ग्राम पंचायत।
- **नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (NDRGGSP)** - कोटा जिले की लाडपुरा ब्लॉक पंचायत में जाखोरा ग्राम पंचायत

वन स्टॉप शॉप OSS प्रणाली

14 जुलाई, 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों के त्वरित अनुमोदन एवं अनुमति के लिए 'वन स्टॉप शॉप' प्रणाली की स्थापना से सम्बन्धित निर्णय लिया गया है। इस प्रणाली से उद्यमी सुगमतापूर्वक अपनी इकाईयाँ स्थापित कर सकेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद ने इसके लिए राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन अधिनियम-2011' में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक निवेश बोर्ड का गठन किया जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर भी उपलब्ध हो सकेंगे।

'प्लग एण्ड प्ले' कंसेप्ट को मंजूरी

16 जुलाई, 2020 को राजस्थान सरकार ने पहली बार 'प्लग एण्ड प्ले' कंसेप्ट और छोटे औद्योगिक भूखण्ड पैटर्न को लागू किया है। इसके अंतर्गत औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के लिए रीको स्वयं अत्याधुनिक इमारत उपलब्ध करायेगा। इस कांसेप्ट के माध्यम से कम पूँजी में कारोबार को आगे बढ़ाया जा सकेगा। 'प्लग एण्ड प्ले' अर्थात 'आओ और शुरूआत करो का पायलट प्रोजेक्ट सीतापुरा (जयपुर) के स्पेशन इकानॉमिक जोन में शुरू किया गया है।

विश्व बैंक ने भारत में STARS कार्यक्रम के लिए मंजूर की 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि

28 जून, 2020 को विश्व बैंक समूह ने भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए STARS(Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program) कार्यक्रम को 500 मिलियन डॉलर (लगभग 3700 करोड़ रुपये) के ऋण को मंज़ूरी दी है। स्वीकृत ऋण से भारत के 6 राज्यों राजस्थान, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र लाभान्वित होंगे। STARS कार्यक्रम से भारत और विश्व बैंक के बीच की साझेदारी मजबूत होगी तथा सार्वजानिक स्कूल शिक्षा को मजबूत करके भारत के "सभी के लिए शिक्षा" लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

स्मार्ट क्लास के लिए समझौता ज्ञापन

प्रदेश की सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए राजस्थान सरकार ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड के बीच त्रिपक्षीय सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये है। इसके अंतर्गत 100 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये जायेंगे और कक्षा 1 से 12वीं तक पाठ्यक्रम को ई-कंटेंट के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। इस परियोजना पर लगभग 1.85 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

डेयरी अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन

महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MPUAT) उदयपुर तथा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) करनाल के मध्य समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किया गया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान और प्रशिक्षण की प्रगति को बढ़ावा देना तथा डेयरी पशुओं की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाना है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा शासित NDRI, डेयरी अनुसंधान पर भारत का प्रमुख संस्थान है।

राजस्थान विधानसभा में डिजिटल संग्रहालय के लिए राज्य सरकार ने समितियों का गठन किया

राज्य सरकार ने राजस्थान विधानसभा परिसर में निर्मित किए जाने वाले डिजिटल संग्रहालय के कार्यों की दिशा, गति, पर्यवेक्षण और प्रमाणीकरण के लिए एक अंतर-विभागीय अनुसंधान समिति और एक तकनीकी समिति का गठन किया है।
डिजिटल संग्रहालय में, राज्य की राजनीतिक कथा, लोकतंत्र, आधुनिक राजस्थान का गठन और राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के योगदान के साथ-साथ उन निर्माताओं के योगदान को भी दिखाया जाएगा जो राजस्थान राज्य के

निर्माण में भागीदार थे। 19 जुलाई 2019 को बजट घोषणा पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान विधानसभा में आधुनिक डिजिटल संग्रहालय बनाने की घोषणा की थी।

किसानों के लिए रियायती ऋण

कोरोना महामारी के बीच किसानों को संकट से बचाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 जून से किसानों को 3 फीसदी ब्याजदर पर लोन देने की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को अपनी फसल गिरवी रखने पर मात्र 3 फीसदी ब्याज दर पर लोन मिल सकेगा। इस लोन का 7 फीसदी ब्याज दर सरकार वहन करेगी। इसमें लघु और सीमांत किसानों के लिए 1.5 लाख रुपये और बड़े किसानों के लिए 3 लाख रुपये की ऋण राशि होगी। ब्याज दर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किसान कल्याण योजना से 50 करोड़ रुपये आवंटित किये जायेंगे।

वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड

जून, 2020 को राजस्थान सरकार ने एक आदेश जारी कर 'वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड' की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार करने हेतु राज्य-स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का कार्यकाल 6 माह का होगा।

समिति की संरचना

- संयोजक: डॉ.अनुला मौर्य
- सदस्य: डॉ.सुषमा सिंघवी, डॉ. राजकुमार जोशी, रामसिंह चौहान, फिरोज अख्तर, एनएस बिस्सा, राम प्रसाद महाराज
- सदस्य सचिव: निदेशक, संस्कृत शिक्षा
- प्रशासनिक विभाग: संस्कृत शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

नशा मुक्त भारत कार्य योजना शुरू

26 जून 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने विश्व मादक द्रव्य एवं मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 देश के 272 जिलों में लागू की।

मुख्य बिंदु:

- नशा मुक्त भारत अभियान के तहत गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से व्यापक स्तर पर जन जागरुकता अभियान चलाया जाएगा। अभियान का मुख्य जोर नशे के आदी लोगों का इलाज करवाकर उनका पुनर्वास करने पर होगा।

- जन जागरुकता अभियान के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशा मुक्ति में कार्यरत संस्थानों के लिये धन जुटाने तथा युवाओं के बीच नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिये कॉलेजों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा।
- विश्व मादक द्रव्य एवं मानव तस्करी विरोधी दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्ति अभियान का लोगो व टैग लाइन 'नशा मुक्त भारत-सशक्त भारत' भी जारी किया गया।

नशा मुक्त भारत: राजस्थान के जिले

- राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को 272 सर्वाधिक प्रभावित जिलों की सूची में शामिल किया गया है इन जिलों पर नशा मुक्त भारत वार्षिक कार्य योजना 2020-21 के तहत ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

चित्तौड़गढ़	**जोधपुर**	**अजमेर**	**बीकानेर**	**सवाईमाधोपुर**
प्रतापगढ़	बाड़मेर	सीकर	बांसवाड़ा	करौली
झालावाड़	जैसलमेर	झुंझुनू	भरतपुर	सिरोही
भीलवाड़ा	पाली	अलवर	बूंदी	टोंक
उदयपुर	जालोर	हनुमानगढ़	चूरू	दौसा
कोटा	नागौर	श्रीगंगानगर	डूंगरपुर	
बारां	जयपुर	ब्यावर (अजमेर जिले में शहर)	राजसमंद	

राजस्थान में 16 नयी नगर पालिकाओं का गठन

जून 2020 में, स्थानीय स्वशासन विभाग ने राजस्थान में 16 नई नगरपालिकाओं के गठन की घोषणा की। जिन जिलों में नई नगरपालिकाएँ बनाई गई हैं वे हैं -

- जयपुर - बस्सी और पावटा नगर पालिका

- अलवर - लक्ष्मणगढ़ और बंसूर नगर पालिका
- दौसा - मंडावरी नगर पालिका
- जोधपुर - भोपालगढ़ नगर पालिका
- सिरोही - जावाल नगर पालिका
- भरतपुर - सिकरी और उच्चैन नगर पालिका
- करौली - सपोटरा नगर पालिका
- कोटा - सुल्तानपुर नगर पालिका
- श्रीगंगानगर - लालगढ़-जातां नगर पालिका
- बारां - अटरू नगर पालिका
- धौलपुर - सिरमथुरा और बसेड़ी नगर पालिका

वृक्षारोपण महाअभियान

- थीम -> एक मिनख-एक पेड़
- राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,जोधपुर द्वारा सम्पूर्ण राज्य में 15 अगस्त, 2020 से 9 दिवसीय वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन किया गया जिसका समापन 23 अगस्त, 2020 को हुआ।
- वृक्षारोपण अभियान के दौरान समस्त जिलों में तालुका स्तर से लेकर जिला मुख्ययालय स्तर तक पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यत न्यायालय परिसरों, लीगल सर्विसेज क्लिनिक, स्थानीय निकाय, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, राजकीय कार्यालयों, जेल आश्रय-गृह इत्यादि स्थानों पौधारोपण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया
- विभिन्न स्थानों पर पौधा वितरण केन्द्रों की स्थापना की गई तथा आमजन को अभियान से जोेड़ने हेतु नीवन माध्यम अपनाते हुए राजस्थान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नम्बर पर मिस्ड काल कर उन्हें जोड़ने का तरीका अपनाया गया।
- इस महाअभियान के दौरान सम्पूर्ण राजस्थान में कुल 17,566 स्थानों पर 18,464 पौधे लगाए गए। तथा 1 लाख से ज्यादा पौधों का हुआ वितरण किया गया।

नजूल सम्पत्तियों के लिए गठित समिति में अब सहायक पुलिस आयुक्त सदस्य होंगे

8 अगस्त, 2020 को राज्य सरकार द्वारा जयपुर शहर में नजूल सम्पत्तियों का कब्जा लेने के लिए गठित समिति में सम्बन्धित क्षेत्र के उप पलिस अधीक्षक के स्थान पर सहायक पुलिस आयुक्त को सदस्य के रूप में

सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है। नजूल सम्पत्तियों का कब्जा लेने के लिए सम्पदा निदेशालय ने अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन, जयपर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।
कारण- जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली के अस्तित्व में आने के बाद पुलिस उप अधीक्षक का पदनाम सहायक पुलिस आयुक्त हो गया है। इसलिए उक्त समिति के गठन में संशोधन कर पुलिस उप अधीक्षक के स्थान पर सहायक पुलिस आयुक्त को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

अगस्त क्रांति सप्ताह

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में 9 अगस्त से 15 अगस्त 2020 तक विभिन्न आयोजनों की श्रृंखला में 'अगस्त क्रांति सप्ताह' का आयोजन किया गया।
'अगस्त क्रांति सप्ताह' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में ब्लॉक स्तर एवं उपखण्ड स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन किया गया।

कोरोना वारियर्स सम्मानित

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किए गए 'अगस्त क्रांति सप्ताह' के तहत 11 अगस्त, 2020 को नगर निगम मुख्यालय के सभासद भवन में आयोजित सम्मान समारोह में नगर निगम के फ्रन्ट लाईन पर ड्यूटी करने वाले 79 कोरोना वारियर्स/सफाई कर्मचारियों को प्रशस्ति-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया।

स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कस

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों के कल्याण व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए 'स्टेट सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स' का निर्णय लिया। उन्होंने 4 अगस्त, 2020 को शीघ्र इस बोर्ड का गठन करने के निर्देश दिए। यह बोर्ड इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेगा।

पोषण वाटिका अभियान

कुपोषण मुक्त, स्वस्थ और मजबूत भारत बनाने के उद्देश्य से 30 जुलाई से 15 अगस्त,2020 तक राज्य में 'पोषण वाटिका अभियान' का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती ममता भूपेश ने 28 जलाई, 2020 को समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय में आँवला, अमरुद, चीकू, बील आदि फलदार पौधों का आरोपण कर 'पोषण वाटिका अभियान' का शुभारम्भ किया था।

30 जुलाई से 15 अगस्त तक के पखवाड़े में विभाग के लगभग 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों में से विकास के लिए चयनित सभी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। विभाग में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर फलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनके साथ ही चयनित केंद्रों पर क्यारियाँ बना कर मौसमी सब्जियों को भी लगाया जाएगा। इनका उद्देश्य पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्र में वाटिका बनाने के साथ साथ जनसामान्य को पोषण के प्रति जागरूक करना भी है।

राजस्थान की पहली राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National legal Services Authority- NALSA) के तत्वावधान में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (Rajasthan State Legal Services Authority-RSLSA) ने 22 अगस्त, 2020 को राज्य की पहली ऑनलाइन लोक अदालत (E-Lok adalat) का आयोजन किया।
प्रदेश की इस पहली ई-लोक अदालत का आयोजन पूरे राज्य में किया गया था, जिसमें बाड़मेर, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, और सिरोही जैसे इलाके जहां पर नेटवर्क मिलना बड़ी समस्या है वहां पर भी लोक अदालत का आयोजन सफलता पूर्वक हुआ है।
राज्य स्तरीय ऑनलाइन लोक अदालत के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नाल्सा (NALSA) के कार्यकारी अध्यक्ष एन.वी.रमन्ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्याधीश अजय रस्तौगी एवं दिनेश माहेश्वरी सहित राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इंद्रजीत महंति, संगीत लोढ़ा सहित नाल्सा एवं राल्सा के पदाधिकारी, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पदाधिकारी तथा अन्य न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे।
इस ई-लोक अदालत में 47,654 मामले उठाए गए, जिनमें से 33,476 मामलों का निपटारा किया गया। मुकदमों की सुनवाई के लिए 350 बेंचों का गठन किया गया। सुलझाए गए मामलों में से 29,092 मुकदमे अदालतों में लम्बित थे और 4,384 मामलों को प्रीलीटेशन स्टेज पर सुलझाया गया था।

राज्य विधानसभा में राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक, 2020 सहित अनेक विधेयक पारित

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान पुलिस (संशोधन) विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। संसदीय कार्य मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा की विधेयक के तहत् पुलिस और आमजन के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए 'ग्राम रक्षक' नियुक्त किए जाएंगे, जिनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है। इनका कार्यकाल दो वर्ष का होगा तथा धारा 53 के तहत् इन्हें उचित मानदेय देय होगा।
इस संशोधित विधेयक के माध्यम से 'राजस्थान पुलिस अधिनियम 2007' की तीन धाराओं में परिवर्तन किया गया है।
14 अगस्त, 2020 को बुलाये गए राजस्थान विधानसभा के 5वें सत्र में उपर्युक्त विधेयक के अतिरिक्त कई अन्य विधेयक भी पारित हुए जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

- राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम-सीमा अधिरोपण (संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान कृषि उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, राजस्थान माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान महामारी विधेयक, 2020
- राजस्थान स्टांप (संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान विशेष न्यायलय (निरसन) विधेयक, 2020
- राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2020
- रजिस्ट्रीकरण (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
- राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020
- राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास (संशोधन) विधेयक, 2020

राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक, 2020

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान मदरसा बोर्ड विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड के द्वारा दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम एवं आधुनिक तकनीकी शिक्षा के समायोजन से उर्दू अध्ययन व शिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। 2003 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। अब इस विधेयक से मदरसों को वैधानिक दर्जा मिल पायेगा। इससे प्रदेश में 1 लाख 94 हजार अध्ययनरत बच्चों को दी जा रही तालीम की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।

राजस्थान महामारी विधेयक, 2020

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा की राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 संक्रामक रोगों के फैलाव के निवारण हेतु उपबंध करता है। किन्तु इस महामारी की रोकथाम हेतु निवारक और उपचारात्मक उपाय करने के लिए और अधिक सुधारात्मक कदम उठाये जाने आवश्यक थे। इसलिए राज्य सरकार ने महामारी के विनियमन और रोकथाम के लिए और अधिक प्रभावी तथा कठोर उपाय करने के लिए एवं विद्यमान राजस्थान संक्रामक रोग अधिनियम, 1957 को निरसित करने के लिए राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 प्रख्यापित किया था।

तत्पश्चात जनता को वृहद् स्तर पर राहत प्रदान करने के लिए राजस्थान महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 द्वारा उक्त अध्यादेश की धारा 11 संशोधित की गयी थी। उक्त दोनों अध्यादेशों को समेकित करने के पश्चात् राजस्थान महामारी विधेयक, 2020 पारित किया गया।

राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विशेष न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा की केन्द्र सरकार द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में नई धारा 18 क के जोड़ने के फलस्वरूप इस अधिनियम ने अपना अस्तित्व खो दिया है।
अब केन्द्रीय अधिनियम के प्रचलन में आने के कारण राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं.38) को निरसित करने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया है।

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। तत्पश्चात व्यापारियों द्वारा अन्य राज्यों से राज्य के मण्डी क्षेत्र में लाई गई अधिसूचित कृषि उपज पर मण्डी फीस का संदाय सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2020 लाया गया है।

राजस्थान माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2020

केन्द्र सरकार द्वारा जीएसटी एक्ट में संशोधन के अनुरूप ही राज्य सरकार यह संशोधन ले कर आई है। माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 अधिनियम के जो प्रावधान थे उनकी निर्धारित समयावधि में पालना करने में कठिनाई हो रही थी, इसीलिए इस समय को बढ़ाया गया। युद्ध, महामारी, भूकम्प और बाढ़ जैसी विशेष परिस्थितियों में अधिसूचित समय सीमा बढ़ाने की शक्तियां राज्य सरकार को दी गई है। इस अधिनियम के 13 खण्डों में संशोधन किए गए हैं। विधेयक में कंपोजिशन स्कीम, प्रक्रियागत सरलीकरण, वॉलेन्टीयर रजिस्ट्रेशन के केन्सीलेशन तथा आइटीसी का उपयोग करने के लिए समय सीमा में संशोधन किया गया है।

राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा की इस विधेयक में प्रस्तावित है कि धारा 3-ख के अधीन संगृहीत अधिभार, जो कि गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, का उपयोग सूखा, बाढ़, महामारी, लोक स्वास्थ्य अत्यावश्यक्ताओं, अग्नि इत्यादि जैसा प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं के शमन के प्रयोजनों के लिए भी किया जाएगा।

राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020

24 अगस्त, 2020 को राजस्थान विधानसभा में राजस्थान उद्यम एकल खिड़की सामर्थ्यकारी और अनुज्ञापन (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित किया गया। उद्योग मंत्री श्री परसादी लाल मीणा ने चर्चा के लिए विधेयक को सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा की राज्य सरकार ने प्रदेश में उद्योगों के अनुकूल माहौल बनाने के लिए 2011 में सिंगल विंडो एक्ट बनाया था। औद्योगिक सलाहकार समिति द्वारा इसे और ज्यादा प्रभावी बनाने की सिफारिश पर इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन किया जा रहा है। इससे निवेशकों को ज्यादा सुविधाएं मुहैया होगी।

राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी नियमों में संशोधन

- राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर पूर्व में स्थापित 'राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006' का नाम परिवर्तन कर 'राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2020' कर दिया गया है।
- गृह विभाग की ओर से इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) नियम, 2006 के अन्तर्गत मौजूदा प्रपत्र-II एवं प्रपत्र-v में वर्णित अभिव्यक्ति 'जिला पुलिस अधीक्षक' के स्थान पर 'जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त' शब्द प्रतिस्थापित किये गये हैं।

प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सियों पर अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन जैसे शब्द लगाने पर पाबंदी

- इसी तरह उपर्युक्त जारी अधिसूचना के नियम-5 में कहा गया है। कि ऐसी किसी भी एजेंसी, पार्टनरशिप फर्म या कम्पनी जिनके नामों में डिटेक्टिव, इंवेस्टीगेशन, सर्वीलियन्स, इंटेलीजेन्स, इंटेरोगेशन, फेसेलिटी, लेबर सप्लायर जैसे शब्द शामिल हों, उन्हें लाईसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
- इसका आशय यह है कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सियाँ अब अपने नाम के साथ डिटेक्टिव, इंवेस्टिगेशन, सर्विलांस, इंटेलीजेंस, इंट्रोगेशन, फैसेलिटी तथा लेबर सप्लायर आदि शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी क्योंकि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सियों द्वारा इन शब्दों के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी गई है।
- वर्तमान कार्यरत एजेन्सियाँ जो इस प्रकार के शब्द अपने नाम में प्रयोग कर रही हैं उन्हें भी एक माह के अन्दर वर्जित शब्दों को हटाने की कार्यवाही करनी होगी।
- राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के साथ ही उपरोक्त वर्णित वर्जित शब्दों के साथ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी के नवीन लाइसेंस नवीनीकरण जारी नहीं किए जाएंगे।जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेन्सी

एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन करेंगे, उन्हें उपरोक्त शब्दों को हटाकर ही अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार

राजस्थान सरकार द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की कक्षा 8, 10 एवं 12 की परीक्षाओं में जिलेवार अलग-अलग संकायों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली 1,208 बालिकाओं को कुल 9,92,45,000 रु की 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार' राशि प्रदान की गई है।
इन्दिरा प्रियदर्शिनी योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक निःशक्तजन, सामान्य वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग एवं बीपीएल वर्ग में जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली एवं संस्कृत शिक्षा में इन वर्गों की राज्य में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश की बालिकाओं को 'इन्दिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

पुरस्कार राशि:

- कक्षा 8 की बालिकाओं को - 40 हजार
- कक्षा 10 की बालिकाओं को - 75 हजार
- कक्षा 12 की पात्र चयनित बालिकाओं को - एक लाख रुपए

राजस्थान कॉउन्सिल ऑफ स्कूल एजुकेशन

- राजस्थान सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए प्री-प्राइमरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के समेकित विकास के लिए एक नए बोर्ड का गठन किया है। सरकार के निर्णय के तहत 'राजस्थान कॉउन्सिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन' और 'राजस्थान कॉउन्सिल ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन' को एक साथ मिला दिया है तथा अब इनके स्थान पर एकीकृत 'राजस्थान कॉउन्सिल ऑफ स्कूल एजुकेशन' का गठन कर दिया गया है।
- 28 जुलाई, 2020 को राज्य शिक्षा मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस पर विधिवत सहमति जताते हुए यह निर्णय लिया गया। इस प्रकार प्रदेश में अब प्री-प्राइमरी से उच्च माध्यमिक स्कूल शिक्षा के लिए अब एक ही संस्था कार्य करेगी।
- राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा जारी की गई एकीकृत स्कूल शिक्षा योजना के क्रम में राजस्थान कॉउन्सिल ऑफ स्कूल एजुकेशन का गठन किया है, इसी के अन्तर्गत अब परिषद् के वर्तमान विधान में संशोधन कर उसके स्थान पर भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रस्तावित 'राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्'

का विधान अंगीकार किया गया है। इसी क्रम में दोनों परिषदों के उद्देश्यों एवं गतिविधियों को राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् में समाहित किया गया है।

शुद्ध के लिए युद्ध अभियान

8-14 जुलाई, 2020 को प्रदेशवासियों को मिलने वाले दूध व दूध से बने उत्पादों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए सम्पूर्ण राज्य में 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' चलाया गया। इस अभियान के दौरान व्यापक स्तर पर डेयरी उत्पादों के नमूनों की जाँच की गई।

अमृता अभियान

14 मई 2020 को राजस्थान राज्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अंतर्गत राजस्थान राज्य औषध पादप मंडल के तत्वावधान में प्रदेश में गिलोय रोपण अभियान 'अमृता' का शुभारंभ किया ।

इस अभियान के तहत जयपुर जिले में अगले 4 महीनों में लगभग डेढ़ लाख गिलोय के पौधे लगाए जाएंगे। गिलोय एक सुरक्षित औषधि है तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को ध्यान में रखते हुए गिलोय अत्यंत उपयोगी है।

eSanjeevaniOPD: नि:शुल्क चिकित्सा दूरसंचार सेवा

4 मई 2020 को कोरोना संक्रमण के चलते राजस्थान के राज्य स्वास्थ्य मंत्री श्री रघु शर्मा ने जिले में ई-संजीवनी ओपीडी सेवा प्रारंभ की है। इससे आमजन घर बैठे डॉक्टरों से स्वस्थ सम्बन्धी परामर्श ले सकते है। इस सेवा से सुलभता और सरलता से निशुल्क परामर्श मिलेगा। वर्तमान में राज्य भर में 100 स्वास्थ्य संस्थानों को इस से जोड़ा गया है जिसमे 30 डॉक्टरों की टीम इन सेवाओं को वेब-पोर्टल के माध्यम से प्रदान कर रही है। ई-संजीवनी ओपीडी सेवा में विभिन्न अस्पतालों के चिकित्सक सुबह 8.30 बजे से दोपहर 2 बजे तक निशुल्क परामर्श सेवा देंगे।

ESanjeevani वेब-पोर्टल

- e-Sanjeevani OPD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा द्वारा देश के नागरिकों के लिए विकसित की गई ऑनलाइन सेवा है |
- e-SanjeevaniOPD - Stay Home OPD को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ़ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) मोहाली द्वारा विकसित किया गया है |

- e-SanjeevaniOPD, C-DAC, मोहाली द्वारा विकसित भारत की प्रमुख टेलीमेडिसिन तकनीक eSanjeevani पर आधारित है।

चिकित्सा दूरसंचार सेवा

राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा के माध्यम से एक डॉक्टर और एक मरीज के बीच सुरक्षित और संरचित वीडियो आधारित चिकित्सीय परामर्श उनके घर की परिधि में सक्षम किए जा रहे हैं। लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य सेवाएं चिकित्सीय परामर्श एवं उपचार ई-संजीवनी मे माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी।

E-SanjeevaniOPD में परामर्श की प्रक्रिया

- पंजीकरण
- टोकन
- लॉग इन
- प्रतीक्षा
- परामर्श
- ePrescription

राजस्थान में विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित

- राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है।
- विश्व आदिवासी दिवस पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

RBSC द्वारा 'डीजी लॉकर' लॉन्च

20 अगस्त, 2020 को देश में संचार क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) की 76वीं जयन्ती के मौके पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Rajasthan Board of Secondary Education) ने अंक तालिका, परीक्षा प्रमाण-पत्र या बोर्ड से संबंधित किसी भी प्रमाण पत्र को ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए 'डीजी लॉकर' लॉन्च किया है। इस सुविधा से लगभग 60 लाख छात्रों को मदद मिलेगी जो 2018, 2019 और 2020 के

विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे। डीजी लॉकर में मार्कशीट अपलोड करने से परीक्षार्थियों के प्रमाण पत्र खो जाने या नष्ट होने के कारण होने वाली असुविधा से मुक्ति मिलेगी।

डीजी लॉकर प्रणाली से जुड़ने के लिए, छात्रों को सरकार का 'डीजी लॉकर ऐप 'डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद एप पर अपना मोबाइल नम्बर या आधार नम्बर अंकित कर ओटीपी वेरिफिकेशन कर अपने पसन्द का पिन/पासवर्ड जनरेट करना होगा। पिन/पासवर्ड जनरेशन के बाद लॉगिन कर जरूरी दस्तावेज डाउनलोड कर देखा जा सकता है। वहीं आवश्यकता होने पर उसका प्रिन्ट आउट भी प्राप्त किया जा सकता है।

राजस्थान न्यायिक सेवाओं में MBC और EWS को आरक्षण

राजस्थान सरकार ने (Economically Weaker Section) EWS और MBC (More Backward Classes) वर्ग को न्यायिक सेवा में 1% की जगह 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। अब EWS और MBC वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यायिक सेवा में नियुक्ति के ज्यादा अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य कैबिनेट ने 'न्यायिक सेवा नियम, 2010' में संशोधन को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार ने इन सेवा की भर्तियों में इंटरव्यू प्रक्रिया भी तय कर दी है।

राजस्थान के राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान उच्च न्यायलय के परामर्श से राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 में संशोधन कर नियम बनाए हैं।

नियम:

- आरक्षण के लिए पात्र वर्गों की श्रेणी में 'अधिक पिछड़ा वर्ग, "और" आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग " को सम्मिलित किया जायेगा।
- MBC को 5% आरक्षण तथा EWS को 10% आरक्षण सीधी भर्ती में दिया जायेगा।
- किसी विशेष वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच पात्र और उपयुक्त उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में, उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा।
- संशोधन के तहत अभ्यर्थियों की साक्षात्कार परीक्षा के लिए कमेटी का प्रावधान किया गया है। कमेटी में उच्च न्यायालय के दो सेवारत न्यायाधीश होंगे।इसके अलावा एक विधि विषय का प्रोफेसर होगा। सभी का मनोनयन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की ओर से किया जाएगा।
- न्यायिक सेवा में दिव्यांग आरक्षण का प्रावधान भी लागू होगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS (Economically Weaker Section)

इस नियम के अनुसार "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" में वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के निवासी हैं और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अधिक पिछड़े वर्ग या जिनके परिवार आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम है। आय में सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि से आय शामिल होगी।

MBC (More Backward Classes) वर्ग में इन जातियों को मिलेगा लाभ

- गुर्जर
- रायका-रैबारी
- गाडिया-लुहार
- बंजारा
- गडरिया

सरकारी apps एवं पोर्टल

भारत सरकार द्वारा COVID-19 रोगी ट्रैकिंग के लिए 'आरोग्य सेतु' ऐप

भारत सरकार ने 2 अप्रैल 2020 को COVID-19 ट्रैकिंग हेतु 'आरोग्य सेतु' ऐप लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु एप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार किया है। यह ऐप यूज़र्स को यह जानने में मदद करेगा कि उसे कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा है या नहीं। वह जाने-अनजाने में किसी कोरोना वायरस संक्रमित इंसान के संपर्क में आकर संक्रमित हुआ है या नहीं। COVID-19 ट्रैकर ऐप फिलहाल 11 भाषाओं को सपोर्ट करता है, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी भी शामिल हैं। इसके अलावा यह लोकेशन को एक्सेस करने के लिए ब्लूटूथ का सहारा लेता है।

किसान रथ मोबाइल एप

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानो को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसान रथ मोबाइल एप लॉन्च किया है । कोरोना वायरस के चलते देश में हुए लॉक डाउन के कारण जो किसान अपनी फसलों को बेच नहीं पा रहे थे वे इस मोबाइल ऍप के माध्यम से अपनी फसल को ऑनलाइन बेच सकते है और व्यापारी भी इस मोबाइल ऍप के ज़रिये फसलों का ब्यौरा देख सकते है।

किसान रथ मोबाइल एप के लाभ

- इस किसानरथ मोबाइल एप के ज़रिये फसलों कि खरीद और बिक्री दोनों में आसानी होगी इससे सभी किसानों और व्यापारियों को लाभ होगा।
- इस एप से किसानों और व्यापारियों को परिवहन वाहनों (ट्रक या अन्य सामान ढ़ोने वाला वाहन) के बारे में जानकारी मिलेगी।
- इस मोबाइल एप के माध्यम से ट्रांसपोटर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
- किसान द्वारा दर्ज ढुलाई के माल की मात्रा व्यापारियों और ट्रांसपोर्टरों दोनों को दिखाई देगा।
- कारोबारियों को अपने क्षेत्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध कृषि उपज का पता चल जाएगा और वे विभिन्न किसानों के द्वारा भेजे जा सकने वाले कृषि वस्तुओं को जुटाकर उसे खेत से उठाने के लिए ट्रक की व्यवस्था कर सकते हैं।

- Kisan Rath App पर किसान अपनी फसल को पूरा ब्यौरा भी आसानी से देख सकते है । उसके बाद परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली नेटवर्क कंपनी किसानों को उस माल को पहुंचाने के लिए ट्रक और किराये का ब्यौरा उपलब्ध कराएंगी।
- इस ऍप पर आप कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से खेती की अन्य जरूरतों के लिए मशीनरी भी बुक कर सकते हैं।
- इस मोबाइल ऐप पर 14 हजार से अधिक कस्टम हायर सेंटरों (CHC) के 20 हजार से अधिक ट्रैक्टर भी रजिस्टर्ड हैं। जिससे देश के किसानों के साथ ट्रांसपोर्टरों को भी काम मिलेगा, जिसका दोनों को काफी फायदा होगा ।

जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल विभाग के अंतर्गत भारत फार्मा पीएसयू ब्यूरो (BPPI) द्वारा प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी) के लिए जनऔषधि सुगम मोबाइल ऐप को विकसित किया गया है। यह ऐप एंड्राइड और आई-फ़ोन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उपयोगकर्ता इसे गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं।

इस ऐप में कई सर्विस हैं:

- यूजर्स अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्र के बारे पता सकते हैं तथा जनऔषधि केंद्र तक जाने का रास्ता भी देख सकते हैं
- मार्केट में कौन-कौन सी जेनेरिक दवाएं उपलब्ध उनकी जानकारी हासिल की जा सकती है।
- जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं की कीमत में कितना फर्क है यह भी पता लगा सकते हैं।

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ऐप्स

RajCovidInfo Android ऐप

कोरोना महामारी संबंधित जानकारी, दिशानिर्देश, स्वास्थ्य सलाह, राज्य से संबंधित डेटा, अस्पताल / हेल्पलाइन विवरण और सूचना अलर्ट प्राप्त करने के लिए यह आधिकारिक राजस्थान सरकार ऐप है ।

ई-बाजार COVID 19 मोबाइल ऐप

ई-बाजार COVID-19 ऐप को विक्रेताओं और खरीदारों के मध्य दैनिक आवश्यक वाले किराने के सामान की बिक्री, खरीद और डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

RSMP RajConecT

RSMP RajConecT एक राजस्थान सरकार का मंच है। इस पर आप कोविद-19 से संबंधित विभिन्न सर्वेक्षणों में भाग ले सकते हैं।साथ ही चैट बोट और चैनल के माध्यम से आप कोविद -19 से संबंधित जानकारी के बारे में खुद को अपडेट रख सकते हैं।

ई ग्राम स्वराज पोर्टल

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर देश भर के सरपंचों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई ग्राम स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने e-Gram Swaraj App को भी लॉन्च किया है | इस पोर्टल के माध्यम से पंचायत के विकास कार्यो, उनके खंड और सभी कामकाज की जानकारी देश का कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है |

ई ग्राम स्वराज App

ई ग्राम स्वराज ऍप पंचायतो का लेखाजोखा रखने वाला सिंगल डिजिटल प्लेटफार्म है। इसके माध्यम से भी देश के शहरी और ग्रामीण लोगों द्वारा पंचायतो की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है |

E-Gram Swaraj Portal/App के लाभ

- e-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन को पंचायतो के सुचारु सञ्चालन के लिए शुरू किया गया है।
- इस एप्लीकेशन के द्वारा लोग पंचायत में चल रहे काम पर सरलता से निगरानी रख सकते है व जानकारी प्राप्त कर सकते है।
- इस ऍप और पोर्टल से न केवल पंचायतो की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा बल्कि योजना की व्यापकता भी बढ़ेगी।
- e-ग्राम स्वराज पोर्टल और एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी जैसे सरपंचो ,पंचो , पंचायतो का संचित विवरण ,वित्त विवरण ,परसम्पत्ति का विवरण , पंचायत विकास योजना मिशन अंत्योदय आदि एक ही स्थान पर प्राप्त हो जायेगा।
- e-Gram Swaraj Portal पर डेटा एंट्री की संख्या को तर्कसंगत बनाया गया है | इसमें उपयोगकर्ता के लिए सरल नेविगेशन भी है ।
- पंचायत की जानकारी को सुविधाजनक और तुरंत प्राप्त करने के लिए उपयोगकर्ता नागरिक इस app को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते है ।
- इस ऍप के माध्यम से पंचायत के कार्यकलापों , गतिविधियों ,योजना निर्माण , बजट आवंटन , योजनाओ आदि की निगरानी की जा सकती है ।

राज कौशल पोर्टल - राजस्थान श्रम रोजगार विनिमय का शुभारंभ

6 जून 2020 को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज कौशल पोर्टल - ऑनलाइन राजस्थान श्रम रोजगार विनिमय का उद्घाटन किया।

राज कौशल पोर्टल

राज कौशल पोर्टल के अंतर्गत कॉरोना वायरस लॉक डाउन की वजह से जिन श्रमिकों का रोजगार चला गया है उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस पोर्टल पर वह सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं जिन्हे नौकरी की आवशयकता है साथ ही वह उद्योग भी आवेदन कर सकते हैं जिन्हें श्रमिकों की आवशयकता है। राजस्थान राज कौशल पोर्टल को सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित किया गया है। यह पोर्टल एंप्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरह काम करेगा।

- इस योजना के अंतर्गत बेरोजगार श्रमिकों को रोजगार प्रदान करवाया जाएगा।
- राज कौशल योजना के अंतर्गत संस्था / फर्म / कंपनी / नियोक्ताओं को मजदूर प्रदान कराए जाएंगे।
- इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा।

पोर्टल पर पंजीकरण कैसे करें -

नियोक्ता और मजदूर दोनों के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं

- SSO
- राजकौशल पोर्टल
- ई-मित्र

देववाणी मोबाइल एप

एप डवलपर - मोहम्मद इमरान खान (इन्होने 80 से अधिक शैक्षिक मोबाइल एप तैयार कर मुफ्त में शिक्षा जगत को समर्पित किया है। इन एप का उपयोग पूरी दुनिया में 22 करोड़ लोग कर रहे हैं।)
18 अगस्त, 2020 को राजस्थान के संस्कृत शिक्षा राज्य शिक्षा मंत्री डॉ.सुभाष गर्ग ने शिक्षा संकल में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (SSIERT) महापुरा, जयपुर द्वारा तैयार 'देववाणी मोबाइल एप' का ई-लोकार्पण किया।

देववाणी ऍप के उद्देश्य व लाभ:

- कक्षा, विषय और अध्याय के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कंटेन्ट उपलब्ध करना साथ ही प्रत्येक अध्याय के साथ ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा प्रदान करना।

- सिंगल क्लिक गूगल साइन इन की सुविधा है जिस पर स्टूडेंट्स और टीचर्स का रजिस्ट्रेशन करवाया जायेगा।
- महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए नोटिफिकेशन अलर्ट की सुविधा है।
- समय समय पर क्विज और रिव्यू उपलब्ध करवाए जायेंगे जिनसे छात्र स्व मूल्यांकन कर सकेंगे। लर्निंग फोरम से सवालों के जवाब प्राप्त कर सकेंगे।
- संस्कृत शिक्षा में सूचना और संचार की तकनीक को बढ़ावा मिलेगा।
- संस्कृत शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को ई-लर्निंग व एम-लर्निंग के अवसर उपलब्ध कराना।
- कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों के शिक्षण में हो रही क्षति की भरपाई करना।

'स्टुडेन्ट विण्डो', 'टॉक टू टीचर-इन्टरफेस तथा 'NICCI-चैट-बोट' का लोकार्पण

- 28 जुलाई, 2020 को शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने शिक्षा संकुल स्थित सभागार में विद्यार्थियों के प्रश्नों और जिज्ञासाओं के त्वरित ऑनलाईन समाधान हेतु शाला दर्पण पर 'स्टूडेन्ट विण्डो' के रूप में 'टॉक टू टीचर- इंटरफेस', शिक्षकों की परिवेदनाओं, स्थानान्तरण आदेश आदि से सम्बन्धित ट्रेकिंग सिस्टम 'स्टाफ विण्डो' के विस्तार और 'एनआईसीसीआई-चैट-बोट' की ऑनलाईन शुरुआत की गई।
- शिक्षा विभाग में शाला दर्पण पर प्रारम्भ इस ऑनलाईन व्यवस्था से विद्यार्थियों, शिक्षकों और आमजन को शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सूचनाओं और ज्ञान का वृहद स्तर पर लाभ मिल सकेगा।
- शाला दर्पण पोर्टल पर प्रारम्भ 'स्टूडेन्ट विण्डो' पर विद्यार्थी किसी भी विशेषज्ञ शिक्षक से लिखित ऑनलाइन संवाद कर अपनी पढ़ाई सम्बन्धित समस्या का समाधान और अपने जिले के उस विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञ शिक्षक से उत्तर प्राप्त कर सकेंगे।
- अगस्त 2019 में शाला दर्पण पोर्टल पर शिक्षकों के सेवा सम्बन्धित प्रकरणों, स्थानान्तरण प्रार्थनाओं, परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए 'स्टाफ विण्डो' प्रारम्भ की गई थी। इसी स्टाफ विण्डो को और अधिक विकसित करते हुए शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित व्यक्तिगत परिवेदनाओं यथा नियमितिकरण, स्थाईकरण, एसीपी, पेंशन, एसआई एवं जीपीएफ, वेतन स्थिरीकरण, बकाया वेतन, ऐरियर, पदोन्नति पात्रता एवं वरिष्ठता सूची, एसीआर, अवकाश स्वीकृति, प्रशिक्षण, कार्यस्थल उत्पीड़न आदि के आवेदन और निस्तारण ट्रेकिंग के लिए शाला दर्पण NIC टीम द्वारा निर्मित ऑनलाईन मॉड्यूल विकसित किया गया है।
- इसी तरह शाला दर्पण पोर्टल के उपयोग के विभिन्न बिन्दुओं और समस्याओं के बारे में त्वरित ऑटोमेटेड जानकारी, समाधान उपलब्ध करवाने के लिए NIC द्वारा पोर्टल पर एडवांस तकनीक युक्त 'चैटबोट' की शुरुआत की गई है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020

केंद्र सरकार ने 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020' (National Education Policy- 2020) को मंज़ूरी दी है। नई शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' [National Policy on Education (NPE),1986] को प्रतिस्थापित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020, 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। वर्ष 1968 और 1986 के बाद यह भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। NEP-2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है।

- अध्यक्ष: सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पूर्व इसरो प्रमुख पद्म विभूषण डॉ. के कस्तूरीरंगन
- समिति: कस्तूरीरंगन समिति
- समिति का गठन: जून, 2017 में किया गया तथा मई, 2019 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा' कैबिनेट को प्रस्तुत किया गया।
- मंजूरी: 29 जुलाई, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा इसे मंजूरी मिली।

शिक्षा मंत्रालय

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (Ministry of Human Resource Development- MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया है। 1985 से पहले यह मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय ही था जिसे 1985 में बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) कर दिया गया था।

उद्देश्य

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का उद्देश्य शिक्षा की पहुँच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना है।
- छात्रों को जरूरी कौशलों एवं ज्ञान से लैस करना और विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इण्डस्ट्री में कुशल लोगों की कमी को दूर करते हुए देश को ज्ञान आधारित सुपर पॉवर के रूप में स्थापित करना है।
- शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना।
- भाषाई बाध्यताओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों के लिये शिक्षा को सुगम बनाने आदि के लिये तकनीकी के प्रयोग को बढ़ावा देने पर बल देना।

स्कूली शिक्षा में सुधार

नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है।

नया फॉर्मेट	चरण	आयु	कक्षा स्तर
5	फाउण्डेशन स्टेज	3 से 6 वर्ष	आँगनबाड़ी
		6 से 8 वर्ष	नर्सरी (प्री प्राइमरी)
3	प्राथमिक शिक्षा	8 से 11 वर्ष	कक्षा 3 से 5
3	माध्यम स्तर	11 से 14 वर्ष	कक्षा 6 से 8
4	अंतिम स्तर	14 से 18 वर्ष	कक्षा 9 से 12

शिक्षण प्रणाली में सुधार:

- उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी उपलब्ध करवाने के लिए उच्च साधन सम्पन्न एवं बहु विषयक संस्थानों में रूपान्तरित किया जाएगा।
- पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं होती थी, बच्चा 6 वर्ष की आयु से पढ़ना प्रारम्भ करता था लेकिन अब 3 वर्ष से ही शिक्षा ECCE (Early Childhood Care and Education) द्वारा प्रारम्भ (ऑगनबाड़ी के माध्यम से)।
- कक्षा तीन तक के छात्रों को मूलभूत साक्षरता तथा अंकज्ञान (NMSL-National Mission on foundational Literacy &Numeracy) सुनिश्चित किया जाएगा।
- पहले जहाँ कक्षा 11 से विषय चुन सकते थे अब छात्रों को कक्षा 9 से विषय चुनने की आजादी रहेगी।
- कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई में किसी विषय के प्रति गहरी समझ तथा बच्चों की विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाकर जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
- 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव कर अब वर्ष में दो बार (सेमेस्टर प्रणाली द्वारा) ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में परीक्षा आयोजित की जाएँगी ।
- NEP-2020 के तहत मिड-डे मील के साथ नाश्ता देने की भी बात कही गई है। सुबह के समय पोषक नाश्ता अधिक मेहनत वाले विषयों की पढ़ाई में लाभकारी हो सकता है।

शिक्षकों से सम्बंधित सुधार:

- ***नेशनल मेंटरिंग प्लान***- इससे शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा।

- शिक्षकों को प्रभावकारी एवं पारदर्शी प्रक्रियाओं के जरिए भर्ती किया जाएगा तथा पदोन्नति भी अब योग्यता (शैक्षणिक प्रशासन व समयसमय पर कार्य प्रदर्शन का आकलन) आधारित होगी।
- शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा वर्ष 2022 तक राष्ट्रीय प्रोफेशनल मानक (NPST) तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक स्कूल में शिक्षक-छात्रों का अनुपात (PTR)30 : 1 से कम हो तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में यह अनुपात 25 : 1 से कम हो।
- प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वह स्वयं व्यावसायिक विकास (पेशे से सम्बन्धित आधुनिक विचार, नवाचार और खुद में सुधार करने) के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष 50 घण्टों का सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) कार्यक्रम में हिस्सा लें।
- शिक्षकों को गैर-शिक्षण गतिविधियों (जटिल प्रशासनिक कार्य, Mid Day Meal) से सम्बन्धित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव।
- ECCE शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए NCERT द्वारा 6 माह (जो आँगनबाड़ी कर्मचारी 10 +2 या अधिक योग्यता) एवं 1 वर्ष (जो कर्मचारी कम शैक्षणिक योग्य) का डिप्लोमा कार्यक्रम कराया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education (NCFTE), 2021] का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक शिक्षण कार्य (अध्यापन) के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।
- संविदा शिक्षक रखने की बजाय नियमित शिक्षक भर्ती करने पर जोर।

शैक्षणिक भाषा से सम्बंधित सुधार:

- इस नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाने के महत्व को रेखांकित किया गया है। इसमें तीन भाषा फॉर्मूला यानी कि हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में पढाई करवाई जाएगी।
- NEP-2020 के तहत कक्षा-5 तक की पढ़ाई मातृभाषा/ स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाई जाएगी। जिससे अंग्रेजी भाषा की अनिवार्यता (मैक्याले पद्धति) समाप्त होगी।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परन्तु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव को थोपा नहीं जायेगा।
- ई-पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किए जाएंगे। वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है और एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फ़ोरम (NETF) बनाया जा रहा है।

- बधिर छात्रों के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा (Indian Sign Language- ISL) को पूरे देश में मानकीकृत किया जाएगा।
- छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके तहत इच्छुक छात्रों को छठी क्लास के बाद से ही इंटर्नशिप करवाई जाएगी।
- 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा।
- भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिये एक "भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान" तथा "फारसी, पाली और प्राकृत भाषा के लिये राष्ट्रीय संस्थान" स्थापित किया जायेगा।

उच्च शिक्षा (Higher Education)

- ***बहु-स्तरीय प्रवेश एवं निकासी (Multiple entry & Exit)-*** वर्तमान मे तीन या चार वर्ष के डिग्री कोर्स में यदि कोई छात्र किसी कारण वश बीच में पढ़ाई छोड़ देता है, तो उसे डिग्री न मिलने से इस पढाई का कोई महत्त्व नहीं रहता है। लेकिन अब इसमें निम्न परिवर्तन है :
    - एक वर्ष की पढ़ाई पर - सर्टिफिकेट
    - दो वर्ष की पढ़ाई पर - डिप्लोमा
    - तीन या चार वर्ष पर - डिग्री
- ***एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट-*** इसमें विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जाएगा तथा अलग-अलग संस्थानों में छात्र के प्रदर्शन के आधार पर प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।
- जो छात्र हायर एजुकेशन में नहीं जाना चाहते उनके लिए ग्रेजुएशन डिग्री 3 साल की है किन्तु शोध अध्ययन करने वालों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री अब 4 साल की होगी।
- पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एक साल बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प रहेगा तथा पाँच साल का संयुक्त ग्रेजुएट-मास्टर कोर्स लाया जाएगा।
- ***कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) -*** उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एग्जाम होगी जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराएगी। संस्था के लिए यह प्रवेश एग्जाम अनिवार्य नहीं है।
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए अलग-अलग नियम हैं, अब सबमे एक समान नियम बनाया जाएगा। फीस पर नियंत्रण का भी एक तंत्र तैयार किया जाएगा।

- ***अंतर्राष्ट्रीयकरण -*** भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों(शीर्ष 100 में से) को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और नेशनल काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (NCTE)को समाप्त कर रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी।

भारत उच्च शिक्षा आयोग

- भारत उच्च शिक्षा आयोग (Higher Education Commission of India -HECI) को सम्पूर्ण उच्च शिक्षा के सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया जायेगा। इसमें मेडिकल और कानूनी शिक्षा को शामिल नहीं किया जाएगा।
- वर्ष 2040 तक सभी वर्तमान उच्चतर शिक्षा संस्थानों (HEI) का उद्देश्य अपने आपको बहु-विषयक संस्थानों के रूप में स्थापित करना होगा।
- वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में या उसके समीप कम से कम एक बड़ा बहु-विषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित किया जायेगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी और प्रदर्शितापूर्ण निष्पादन के लिये चार संस्थानों/निकायों का निर्धारण किया गया है-
    - विनियमन हेतु- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatory Council- NHERC)
    - मानक निर्धारण- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council- GEC)
    - वित पोषण- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council-HEGC)
    - प्रत्यायन- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council- NAC)

अनुसंधान

- नई शिक्षा नीति में एमफिल (MPhil) को समाप्त किया जायेगा।
- Ph.D के लिए 4 वर्षीय ग्रेजुएशन फिर एम.ए. उसके बाद Mphil) की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाएंगी।
- ***राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन(NRF) -*** राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसन्धान को सही रूप में उत्प्रेरित और विकसित करने के लिए तथा सभी प्रकार के वैज्ञानिक एवं सामाजिक अनुसंधानों पर नियंत्रण रखने के लिए NRF का गठन।

स्कॉलरशिप पोर्टल व खुला विधालय योजना

- SC,ST और OBC के सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉलरशिप पोर्टल का निर्माण किया जाएगा। स्कॉलरशिप प्रदान कर स्कूल न आने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा।
- IIT और IIM की तरह Multidisciplinary Education and Research University (MERUS) की स्थापना की जाएगी।
- देश के जो युवा किसी संस्था में नियमित रूप से अध्ययन नहीं कर सकते उन्हें NIOS (नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग) और राज्यों के ओपन स्कूलों द्वारा चलाए जा रहे ODL (ओपन एण्ड डिस्टेंस लर्निंग) कार्यक्रम से जोड़ कर पढ़ाया जाएगा।
- NIOS (राष्ट्रीय खुला विद्यालय संस्थान)- कक्षा तीन, पाँच और आठ के लिए ओपन लर्निंग की व्यवस्था की जाएगी। ऐसे स्थान जहाँ विद्यालय तक आने के लिए छात्रों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। वहाँ जवाहर नवोदय विद्यालयों के स्तर की तर्ज पर निःशुल्क छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा।
- NEP-2020 में जेंडर इंक्लूजन फण्ड और वंचित इलाकों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर जोर।

परिक्षण तथा मूल्यांकन

- 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षाएँ जारी रहेंगी, बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्र परीक्षा देने के लिए अपने विषयों में से कई विषय चुन सकेंगे।
- छात्रों को वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी जिससे बोर्ड परीक्षाओं के 'उच्चतर जोखिम' पहलू को समाप्त किया जा सके ।
- विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सम्पूर्ण देश में एक समान होगी इसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा साल में 2 बार करवाया जाएगा।
- ***परख*** - छात्रों के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख(PARAKH) नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।
- ***360° Assesment*** - छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360° Assesment के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जायेगा। जिसमे मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक एवं सहपाठियों द्वारा किया जायेगा।

राजस्थान बजट 2020-21

20-02-2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 'सात संकल्पों' पर आधारित ' वित्त वर्ष 2020-21' का राज्य बजट विधानसभा में पेश किया। यह उनका 12वाँ बजट सम्बोधन था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट पेश करते हुए कहा कि, राज्य की माली हालत बहुत हद तक केंद्र की नीतिओं पर निर्भर है। उन्होंने कृषि के लिए 3420 करोड़ रुपये की घोषणा की।

- राजस्थान बजट 2020-21 का अनुमान - 2.25 लाख करोड़।
- केंद्रीय बजट 2020-21 का अनुमान - 30.42 लाख करोड़।

आय				व्यय		
(2,25,000 Cr) उदय योजना				**(2,25,000 Cr) उदय योजना**		
राजस्व		पूंजी		राजस्व		पूंजी
1,73,000 करोड़		**52,000** करोड़		**1,85,000** करोड़		**40,000** करोड़
राज्य कर राजस्व	**77,000** करोड़	ऋण की वसूली	751 करोड़	ब्याज भुगतान	25,000 करोड़	**40,000** करोड़
केंद्रीय कर राजस्व	**47,000** करोड़	सार्वजनिक खाता	25,000 करोड़			
गैर-कर राजस्व	**19,000** करोड़					
केन्द्रीय सहायता	**30,000** करोड़					

केंद्रीय बजट 2020-21 का विश्लेषण

व्यय:

- 2020-21 राजस्थान बजट में 2,25,731 करोड़ रुपये आवंटन है।

- कुल व्यय में से, राजस्व व्यय 1,85,750 करोड़ रुपये (% वृद्धि) और पूंजीगत व्यय 39,981 करोड़ रुपये (% वृद्धि) होने का अनुमान है

प्राप्तियाँ:

- 2020-21 में कुल प्राप्तियां (उधार सहित) 2,25,764 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- कुल प्राप्तियों में से, राजस्व प्राप्तियों का अनुमान 1,73,404 करोड़ रुपये और पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान 52,360 करोड़ रुपये है

बजट घाटा:

बजट अधिशेष

- = राजस्व खाता अधिशेष + पूंजी खाता अधिशेष
- = (राजस्व प्राप्ति- राजस्व व्यय) + (पूंजीगत प्राप्ति - पूंजीगत व्यय)
- = **33 करोड़**।

राजस्व घाटा

- = राजस्व प्राप्ति - राजस्व व्यय
- = **12,345 करोड़**

राजकोषीय घाटा

- = गैर ऋण प्राप्ति - कुल व्यय
- = राजस्व प्राप्ति + ऋणों की वसूली + अन्य प्राप्तियाँ - कुल व्यय।
- = **33,922 करोड़** = **GSDP का 2.99%**

प्राथमिक कमी

- राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
- **8,428 करोड़ रु**

प्राप्तियां:

- कुल 2,25,764 करोड़ रु।
- राजस्व प्राप्तियां (1,73,404 करोड़ रुपये) और पूंजी प्राप्तियां (52,360 करोड़ रुपये) शामिल हैं।

राजस्व प्राप्तियां:

- राज्य का अपना कर राजस्व> केंद्रीय करों में हिस्सा> केंद्रीय अनुदान> गैर-कर राजस्व (वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2020 तक के लिए समान)
- राज्य के अपने कर राजस्व में: GST> बिक्री कर> राज्य का उत्पाद शुल्क> वाहनों पर कर> टिकट और पंजीकरण> बिजली और भूमि राजस्व पर कर और शुल्क> अन्य कर (वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए समान)
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी में:
    - FY 2019-20: कॉर्पोरेशन टैक्स > GST> आयकर > कस्टम ड्यूटी > यूनियन एक्साइज ड्यूटी > अन्य टैक्स > सर्विस टैक्स
    - FY 2020-21: कॉर्पोरेशन टैक्स > GST> आयकर > कस्टम ड्यूटी > यूनियन एक्साइज ड्यूटी > सर्विस टैक्स > अन्य टैक्स

पूँजी प्राप्तियाँ:

- पूंजी प्राप्तियों में सार्वजनिक ऋण, शुद्ध सार्वजनिक खाता, आकस्मिकता निधि से प्राप्त आय के प्रमुख घटक शामिल हैं

व्यय:

- 2020-21 के दौरान कुल = 2,25,731 करोड़।
- इसमें दो घटक शामिल हैं राजस्व व्यय (1,85,750 करोड़ रुपये) और पूंजीगत व्यय (39,981 करोड़ रुपये)।

योजनाएं के उद्व्यय की मुख्य विशेषताएं 2020-21:

आय-व्यय अनुमान 2020-21 में योजना उद्व्यय के अंतर्गत 1,10,200.8 करोड रु. प्रस्तावित किये गए हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	क्षेत्र	प्रस्तावित व्यय	कुल से प्रतिशत
1.	सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाएँ	54767.76	49.70
2.	विद्युत	18505.06	16.79
3.	ग्रामीण विकास	11878.04	10.78
4.	कृषि एवं सम्बद्ध सेवाएँ	9363.89	8.50
5.	यातायात	6834.38	6.20
6.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3620.25	3.28
7.	सामान्य सेवाएँ	2508.78	2.28
8.	आर्थिक सेवाएँ	1881.87	1.53
9.	उद्योग एवं खनिज	951.82	0.86
10.	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	76.20	0.07

11.	**वैज्ञानिक सेवाएँ**	12.77	0.01
कुल		110200.82	100

बजट 2020-21 क्षेत्रवार अध्ययन

सबसे ज्यादा बजट शिक्षा को दिया गया, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस हैल्थ सेक्टर पर रहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के विकास के लिए 7 संकल्पों को प्राथमिकता दी

सात संकल्प:

- पहला संकल्प - निरोगी राजस्थान
- दूसरा संकल्प - संपन्न किसान
- तीसरा संकल्प - महिला बाल व वृद्ध कल्याण
- चौथा संकल्प - सक्षम मजदूर,छात्र,युवा और किसान
- पाँचवा संकल्प - शिक्षा का परिधान
- छठा संकल्प - पानी,बिजली और सड़कों का मान
- सातवां संकल्प - कौशल व तकनीक प्रधान

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ 42 लाख की राजस्व प्राप्तियां
- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में 1 लाख 85 हजार 750 करोड़ 3 लाख का राजस्व व्यय
- वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजस्व घाटा 12 हजार 345 करोड़ 61 लाख
- वर्ष 2020-21 का राजकोषीय घाटा 33 हजार 922 करोड़ 77 लाख जो GSDP का 2.99 प्रतिशत है

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से जुड़े विभागों के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख रुपये का प्रावधान
- 100 करोड़ रुपये के निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष' का गठन
- जिला स्तर पर Early Intervention Centre की स्थापना

- मिलावटखोरों के विरूद्ध कड़े कदम, ऑथोरिटी का गठन, फास्ट ट्रेक कोर्ट
- पीपाड़ सिटी एवं फलोदी के राजकीय चिकित्सालय को जिला चिकित्सालय का दर्जा
- राजकीय चिकित्सालय औसियां में मदर एण्ड चाईल्ड केयर सेंटर
- सांचोर जिला जालोर, सोजत सिटी जिला पाली, लोहावट जिला जोधपुर, तारानगर जिला चूरू एवं बालेसर, भोपालगढ़ जिला जोधपुर में राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेंटर
- Cancer Registry System प्रारम्भ किया जायेगा
- जहां भी पीपीपी मोड संभव वहां के जिला चिकित्सालयों में MRI / CT-Scan सुविधा
- जयपुर, जोधपुर एवं बीकानेर में कैंसर की जांच हेतु PET CT Scan मशीन
- 150 चिकित्सा संस्थानों में डेन्टल चेयर विद एक्स-रे मशीन की स्थापना
- राज्य में कुल 1000 शैय्याओं की वृद्धि |

चिकित्सा शिक्षाः

- 15 नवीन मेडिकल कॉलेज का अगले 4 वर्षों में निर्माण पूर्ण, लगभग 5 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा। इसमें राज्य सरकार की भागीदारी लगभग 2 हजार करोड़ रुपये
- उदयपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध मुख्य चिकित्सालयों को Organ Retrieval Center के रूप में विकसित एवं अधिसूचित करेंगे
- सवाईमानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में गेस्ट्रोसर्जरी विभाग, अंग प्रत्यारोपण विभाग, की स्थापना।
- सवाईमानसिंह चिकित्सालय में न्यूक्लीयर मेडिसिन विभाग की स्थापना एवं 10 करोड़ रुपये की लागत से DSA (Digital Subtraction Angiography) मशीन की स्थापना |
- जोधपुर के एमडीएम अस्पताल में पिडियाट्रिक कैथलैब की स्थापना
- SMS Hospital, Jaipur में G+ 8 मंजिला नया आईपीडी भवन पर 28 करोड़ रुपये खर्च
- जयपुर में राज्य कैंसर संस्थान का सुचारू संचालन
- मथुरा दास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर के OPD ब्लॉक के शेष फ्लोर निर्माण पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अस्पताल में 30-30 बैड के 4 नये वार्ड 11 करोड़ रुपये की लागत से खोले जायेंगे । एक नया न्यूरो इंटरवेंशन लैब । क्षेत्रीय कैंसर सेंटर निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपये का व्यय |

आयुर्वेदः

- अजमेर एवं जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, लगभग 18 करोड़ रुपये का खर्च

- सीकर में 50 शैय्याओं के एकीकृत आयुष चिकि. की स्थापना पर 4 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय |

कृषिः

- विभाग के लिए कुल 3 हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान
- 12500 फार्म पौण्डों के निर्माण पर 150 करोड़ रुपये का व्यय
- 30000 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सूक्ष्म सिंचाई के लिए 91 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 25000 सोलर पंप पर 267 करोड़ रुपये का खर्च
- 2 लाख टन यूरिया तथा 1 लाख टन डीएपी का अग्रिम भंडारण, इस पर 30 करोड़ रुपये व्यय
- 4 वर्षों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, पाली, जालोर, सिरोही एवं झुंझुनूं जिलों के 1500 हैक्टेयर क्षेत्र को खजूर की खेती में लाया जायेगा
- KVSS/GSS के माध्यम से 100 कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना पर 8 करोड़ रुपये का खर्च
- 44 नई स्वतंत्र मंडियां, 100 नवीन गौण उपज मंडी समितियों की स्थापना |

सहकारिताः

- 8 लाख से अधिक पहली बार सदस्य बने किसानों को 1800 करोड़ रुपये का फसली ऋण
- वर्ष 2020-21 में ब्याज अनुदान के रूप में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को 534 करोड़ रुपये
- चार वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन ।
- आगामी वर्ष 500 चयनित पैक्स/लैम्प्स को विकसित कर इन्हें सौर ऊर्जा से जोड़ा जायेगा
- चयनित GSS, KVSS और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम, 22 करोड़ रुपये का व्यय |

पशुपालनः

- अनुदानित दर पर कृत्रिम गर्भाधान हेतु सोर्टेड सीमन की योजना पर 10 करोड़ रूपये व्यय
- 4 हजार पशुपालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा |

महिला एवं बाल विकासः

- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी तथा एएनएम के मध्य बेहतर समन्वय के लिए 'A-3 एप'
- एचसीएम रीपा, जयपुर में इन्दिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जायेगा
- आंगनबाड़ी पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ाने तथा विविधता लाने की कार्यवाही |

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिताः

- विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान
- 'राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के गठन की घोषणा
- प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर पालनहार छात्रावास (हाफ-वे-होम) खोला जायेगा
- 100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष' का गठन
- कॉकलीयर इंप्लांट की अगली कड़ी में बाल्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में ही hearing screening की अनिवार्यता हेतु नीति
- अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, मानसिक विमंदित पुनर्वास गृह, वृद्धाश्रम के आवासियों के मैस भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि
- राजस्थान अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त विकास निगम लिमिटेड' के माध्यम से स्वरोजगार हेतु 50 हजार युवाओं को ऋण |

बजट के प्रमुख बिन्दु - अल्पसंख्यकः

- अजमेर के मसूदा एवं भरतपुर कामां ब्लॉक में 41 करोड़ 60 लाख रुपयों की लागत से अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण
- जिला मुख्यालय नागौर, जिला मुख्यालय सवाईमाधोपुर एवं लाडनूं-नागौर में कुल 3 अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण
- जयपुर में 100 शैय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन निर्माण पर 5 करोड़ रुपये का व्यय
- राजस्थान वक्फ बोर्ड को 5 करोड़ रुपये की ग्रान्ट |

जनजाति विकासः

- जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के उद्देश्य से प्रतापगढ़, डूंगरपुर एवं उदयपुर में कौशल विकास केन्द्र।
- जनजातीय आवासीय विद्यालयों की क्षमता को 1530 से बढ़ाकर 2400 करना, 10 करोड़ रुपये व्यय
- जनजाति क्षेत्र के आवासीय विद्यालय एवं जनजाति छात्रावास के अधीक्षकों के लिए पृथक् कैडर सोलर पम्प हेतु अनुसूचित क्षेत्र के जनजाति किसानों को 45 हजार रुपये प्रत्येक कृषक अनुदान, चरणबद्ध रूप से 5000 किसानों को सोलर पम्प हेतु 22 करोड़ 50 लाख रुपये का व्यय|

युवा मामले एवं खेल:

- राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक एवं जिला स्तरीय खेलों के आयोजन हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
- संविदा पर विभिन्न खेलों के 500 कोच लगाने पर लगभग 10 करोड़ रुपये सालाना का व्यय
- खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में मिलने वाले दैनिक भत्ते की दरों को बढ़ाकर क्रमशः 500 से 1000 रुपये एवं 300 से 600 रुपये करने की घोषणा
- प्रदेश के खिलाड़ी द्वारा ओलम्पिक खेलों, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर ईनामी राशि में वृद्धि |

बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु - उद्योग:

- जोधपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 'राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो' का आयोजन
- रीको द्वारा अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर जिलों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना
- विशेष आर्थिक क्षेत्र-2 सीतापुरा, जयपुर में 25000 व.फी. पर plug and play facility का निर्माण |

गांधी स्मृतिः

- जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना, 10 करोड़ रुपये की लागत
- 144 खादी संस्था/समितियों के कार्यों के कम्प्यूटराईजेशन के लिए सहायता एवं बुनकर संघ के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये |

पैट्रोलियम एवं खनिजः

- दो हजार हैक्टेयर प्रधान खनिज एवं एक हजार हैक्टेयर अप्रधान खनिज के ब्लॉक बनाकर ई-आक्शन
- आगामी वर्ष में 3 Petroleum Exploration Licence (PEL) स्वीकृत
- बाड़मेर जिले में उप निदेशक (पेट्रोलियम) कार्यालय
- जोधपुर व बाड़मेर में Hydrocarbon Sector की स्किल्स में प्रशिक्षण के लिए डेडिकेटेड कौशल केन्द्र |

ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराजः

- 57 नई पं.स. एवं 1456 नई ग्राम पंचायतों हेतु आवश्यकतानुसार नवीन कार्यालय भवन का निर्माण|

बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु - पर्यटनः

- 'Ease of Travelling in Rajasthan' की नीति विकसित करेंगे
- 100 करोड़ रुपये के पर्यटन विकास कोष का गठन
- RTDC की 4 हैरिटेज संपत्तियों के जीर्णोद्धार वं विकास हेतु 4 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 1000 राज्य स्तरीय एवं 5000 स्थानीय स्तर के गाईडों को प्रशिक्षण

शिक्षा:

- वर्ष 2020-21 में कुल 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख रुपये का प्रावधान
- शेष रहे 167 ब्लॉक में प्रत्येक में एक English Medium महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना
- 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय एवं 300 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोले जायेंगे, 25 करोड़ रुपये का व्यय छात्र-छात्राओं के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास हेतु समस्त सरकारी विद्यालयों में शनिवार को No Bag Day रहेगा और कोई अध्यापन कार्य नहीं होगा
- 3 वर्षों में 66 कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की स्थापना, प्रथम चरण में 22 विद्यालय खोले जायेंगे

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा:

- युवाओं में कौशल विकास हेतु Skill Enhancement & Employable Training (SEET) कार्यक्रम
- महाविद्यालयों में वीडियो लेक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कन्टेन्ट बैंक की स्थापना
- MBM Engineering College को upgrade करके विश्वविद्यालय स्तर की सुविधायें प्रदान की जायेंगी

पेयजल:

- जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान 500 जनता जल योजनाओं के माध्यम से 1 लाख घरों को पेयजल से लाभान्वित करने हेतु कुल 750 करोड़ रुपये के पुनर्गठन कार्य । वर्ष 2020-21 में इन पर 100 करोड़ रुपये का व्यय
- वर्ष 2020-21 में 250 गांव में **नल से हर घर में पेयजल आपूर्ति** की योजनाओं के कुल 625 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। 160 करोड़ रुपये का व्यय ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल

उपलब्ध कराने हेतु 16 जिलों की 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ किये जायेंगे। 9 लाख परिवारों को फायदा होगा। लगभग 1 हजार 350 करोड़ रुपये का व्यय

- जयपुर शहर हेतु वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, कुल 165 करोड़ रुपये में से वर्ष 2020-21 में 50 करोड़ रुपये का व्यय

ऊर्जा:

- ऊर्जा विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 18 हजार 530 करोड़ 75 लाख रुपये का प्रावधान
- अल्ट्रा मेगा सौलर पार्क विकसित किये जायेंगे राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम द्वारा लगभग 800 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना जिला मुख्यालय एवं चिन्हित शहरी क्षेत्रों को 'ग्रीन एनर्जी सिटी' के रूप में विकसित किया जायेगा।
- आगामी 5 वर्षों में 300 मेगावाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करेंगे |
- पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 200 छोटी पेयजल परियोजनाओं का सौरकरण
- कुल 50000 कृषि कनेक्शन प्राथमिकता से जारी किये जायेंगे
- किसानों को चरणबद्ध तरीके से दिन के दो ब्लॉक में बिजली दिये जाने के प्रयास ।
- आगामी तीन वर्षों में 220 केवी के 6 नये जीएसएस, 132 केवी के 30 नये जीएसएस, 33 केवी के 287 नये सब-स्टेशन की स्थापना, 1 हजार 500 सब-स्टेशनों की क्षमता में वृद्धि की जायेगी। इन पर कुल 2000 करोड़ रुपये का व्यय।
- वर्ष 2020-21 में 220 केवी के 3 जीएसएस अकलेरा-झालावाड़, रावतसर-हनुमानगढ़ में नये तथा छतरगढ़-बीकानेर में क्षमतावृद्धि पश्चात कमीशन किये जायेंगे
- 132 केवी के 9 नये जीएसएस कमीशन किये जायेंगे।

सार्वजनिक निर्माण विभाग:

- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए वर्ष 2020-21 में कुल 6 हजार 808 करोड़ 63 लाख रुपये का प्रावधान
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज तृतीय में मार्च 2025 तक राज्य की 8 हजार 663 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों का लगभग 4245 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन करवाया जाना
- सर्वाधिक क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण के प्रथम चरण में लगभग 400 करोड़ रुपये का व्यय

परिवहन:

- निजी अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति का उपचार अनिवार्य किया जायेगा।
- सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले श्रेष्ठ तीन जिलों को 'मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार'
- 40 CHC पर Primary Trauma Center, 10 करोड़ रुपये का व्यय
- समस्त प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों में पासपोर्ट सेवा केन्द्र की तर्ज पर Front Office Management System संचालित किये जायेंगे
- जोधपुर जिले के पीपाड़ शहर परिवहन कार्यालय को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा
- प्रत्येक जिले में ट्रेफिक पार्क,16 करोड़ 50 लाख रुपये व्यय किये जायेंगे

जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र विकासः

- जल संसाधन विभाग के लिए कुल 4 हजार 557 करोड़ 87 लाख रुपये का प्रावधान
- बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना (DRIP) के अन्तर्गत आगामी वर्षों में 503 करोड़ रुपये के कार्य ।
- वर्ष 2020-21 में 18 बांधों के जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण तथा सुरक्षा संबंधी कार्य प्रारंभ होंगे
- राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना (RWSRPD) के अंतर्गत 378 करोड़ रुपये के कार्य
- ERCP को सिंचाई एवं जलदाय के लिए top priority में सम्मिलित करने का निश्चय |
- केन्द्र सरकार से ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने का प्रयास ।
- कालीसिंध नदी के अधिशेष जल को बनास नदी में अपवर्तित करने हेतु 602 करोड़ रुपये की लागत से नवनैरा बैराज का निर्माण कार्य प्रगतिरत, 175 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गुड़गांव मुख्य नहर की 23 माईनरों के जीर्णोद्धार के कार्य, 70 करोड़ रुपये की लागत से

स्थानीय निकाय एवं नगरीय विकासः

- प्रदेश के धौलपुर एवं करौली में टाउन हॉल बनवाये जायेंगे
- जोधपुर में ऑडिटोरियम के निर्माण हेतु DPR तैयार करवाई जायेगी
- निकायों द्वारा सीवर सफाई एवं ठोस कचरा प्रबंधन और निस्तारण के लिए उपकरण खरीदे जायेंगे | कुल 176 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित ।
- RUIDP चतुर्थ चरण के अंतर्गत लगभग 2 हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से 7 शहरों में सीवरेज एवं जलप्रदाय कार्य, 6 शहरों में सीवरेज कार्य, 1 शहर में जलप्रदाय कार्य, लगभग 10 लाख लोग लाभान्वित जयपुर के सिविल लाईन फाटक पर 4 लाईन के RoB का निर्माण, लागत 75 करोड़ रुपये

- पुलिस मेमोरियल से मनोचिकित्सालय तक ऐलीवेटेड रोड की डीपीआर का कार्य प्रारम्भ
- JDA द्वारा रामनिवास बाग में दो मंजिले भूमिगत पार्किंग का निर्माण, 100 करोड़ रुपये की लागत
- जोधपुर की जोजरी नदी में साल भर जल की उपलब्धता के लिए तीन STP बनाये जायेंगे आवासन मंडल द्वारा प्रताप नगर, जयपुर में लगभग 65 हजार वर्गमीटर भूमि पर कोचिंग हब
- भीलवाड़ा के न्यास द्वारा कोठारी नदी पर 30 करोड़ रुपये की लागत से हाईलेवल ब्रिज उदयपुर शहर में आयड नदी के पुनःरूद्धार हेतु 75 करोड़ रुपये, पेयजल व्यवस्था हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय
- कोटा में न.वि.न्यास द्वारा अण्डरपास एवं ऐलिवेटेड सड़क का निर्माण, 250 करोड़ रुपये का व्यय
- कोटा में ऑक्सीजोन (सिटी पार्क) के निर्माण पर न्यास द्वारा लगभग 100 करोड़ का व्यय, देवनारायण एकीकृत आवासीय योजना पर अनुमानित व्यय 300 करोड़ रुपये का होगा

कौशल एवं रोजगारः

- समस्त 229 राजकीय ITI में e-Class room के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण
- विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री कौशल मार्गदर्शन योजना
- RKCL द्वारा युवाओं के लिये On-line Digital Skills के कोर्सेज शुरू किये जायेंगे
- 10 करोड़ रुपये के प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष के गठन की घोषणा

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी:

- भरतपुर में एक नवीन क्षेत्रीय विज्ञान कार्यालय खोला जायेगा

सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचारः

- स्टार्टअप्स के विकास के लिए 75 करोड़ रुपये के **राजीव @75 फण्ड'** की स्थापना
- ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम चरणबद्ध तरीके से सभी नगर निकायों में लागू किया जाना |
- Artificial Intelligence Lab की स्थापना की जायेगी
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन-आधार कार्ड के माध्यम से

कला एवं संस्कृतिः

- 22 स्मारकों के पुनरूद्धार के लिए 22 करोड़ 70 लाख रुपये का प्रावधान
- 2 करोड़ ऐतिहासिक अभिलेखों को ऑनलाइन किया जायेगा, 10 करोड़ रुपये का प्रावधान

- श्री जयनारायण व्यास स्मृति भवन, जोधपुर के जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान
- राजस्थान रत्न पुरस्कार योजना को पुनः लागू करने की घोषणा

वन एवं पर्यावरण:

- 5 जिलों हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, अलवर एवं बूंदी में गुरूनानक जयन्ती पार्क
- 'राजस्थान राज्य वन विकास निगम' गठित किया जायेगा

खाद्य एवं नागरिक आपूर्तिः

- जिला रसद कार्यालयों, मुख्यालय एवं गोदामों का कंप्यूटरीकरण, लगभग 16 करोड़ रुपये व्यय
- उचित मूल्य के दुकानदारों को ई-मित्र केन्द्र हेतु अधिकृत करना

सहायता, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सुरक्षाः

- नागरिक सुरक्षा एवं State Disaster Response Force हेतु 10-10 करोड़ रुपये के आधुनिक उपकरण
- प्राकृतिक आपदा के समय निगरानी हेतु समस्त जिला कलक्टर्स को ड्रोन उपलब्ध कराने का निर्णय
- जिलों को 100 अग्निशमन वाहन, रुपये 26 करोड़ की लागत ।
- संचालन हेतु 500 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण
- बाढ़ नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग को 12 करोड़ रुपये, अग्नि नियंत्रण हेतु वन विभाग को 3 करोड़ रुपये |

गृहः

- ERSS का विस्तार करने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान
- माफिया गिरोहों के विरूद्ध अभियान के लिए SOG में दो नई फील्ड यूनिट्स
- SOG में एक नई एण्टी नारकोटिक यूनिट का गठन
- क्षेत्रीय प्रयोगशाला जोधपुर व अजमेर में DNA खंड

सामान्य प्रशासन एवं प्रशासनिक सुधारः

- सरकारी सेवाओं की door step डिलीवरी के लिए जयपुर एवं जोधपुर में पायलट प्रोजेक्ट
- राजस्थान स्टेट फ्लाईंग स्कूल (क्लब), जयपुर को पुनः प्रारंभ किया जायेगा

राजस्व एवं सैनिक कल्याण:

- उपखंड, तहसील, उपतहसील कार्यालयों, आवासों के 35 भवनों के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये
- सीमाज्ञान तथा भू-प्रबन्ध कार्य हेतु 12 आधुनिक सर्वे उपकरण
- 24 जिला सैनिक कार्यालयों में राशि 5 लाख रुपये की दर से कार्यालयों का आधुनिकीकरण
- 14 जिलों में 2 करोड़ 80 लाख रुपये की लागत से शहीद स्मारक निर्माण

देवस्थानः

- वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में समानुपातिक भागीदारी, योजना का विस्तार भी प्रस्तावित

न्याय प्रशासनः

- आगामी वर्ष में 48 नये कोर्ट

कर्मचारी कल्याण:

- जुलाई 2019 से महंगाई भत्ते को 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत किये जाने की घोषणा
- वर्ष 2020-21 में लगभग 53000 पदों पर भर्तियां

अन्य:

- मा. सदस्यों हेतु विधानसभा परिसर के समीप बहुमंजिला आवासीय भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है
- महिला कल्याण नीति, राजस्थान FPO नीति, हस्तशिल्प नीति एवं स्टार्ट-अप नीति ।

बजट 2020-21 के प्रमुख बिन्दु - कर प्रस्ताव

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग:

- राज्य सरकार, स्थानीय निकायों, राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना, सम्पत्ति के बाजार मूल्य (DLC) के स्थान पर, पट्टों पर वसूल की गई राशि पर की जायेगी।

- स्टाम्प ड्यूटी की रियायत से वंचित बीमार सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों को सम्पत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट एवं पंजीयन शुल्क में रियायत दी जायेगी तथा नीलामी में विक्रय पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना नीलामी राशि पर की जायेगी।
- नीमराना, भिवाड़ी, अलवर आदि की भूमियों, विशेषकर ग्रुप हाउसिंग योजनाओं की DLC दरों में विसंगतियाँ दूर की जायेगी।
- लम्बित स्टाम्प प्रकरणों का निस्तारण करने के लिए एमनेस्टी योजना लाकर ब्याज व शास्ति पर शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- उद्योगों की सुगमता के लिए भूमि की वर्तमान DLC को 10 प्रतिशत घटाकर स्टाम्प ड्यूटी की दर केवल 1 प्रतिशत बढ़ाई जायेंगी। वर्ष 2020-21 में भी DLC दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी।
- नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NeSL) के पोर्टल पर ऑनलाईन निष्पादित होने वाले ऋण दस्तावेजों पर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से ऑनलाईन स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की सुविधा दी जायेगी।
- स्टाम्प ड्यूटी की गणना एवं वसूली के लिए राज्य में निष्पादित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए एक माह तथा राज्य के बाहर निष्पादित दस्तावेजों के लिए तीन माह की अवधि निर्धारित की जायेगी।
- भूमि कर (Land Tax) प्रावधानों का सरलीकरण तथा भूमिकर की दरों को तर्कसंगत करके भुगतान की प्रक्रिया को सरल व पारदर्शी बनाया जायेगा।
- बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा निष्पादित ऋण दस्तावेजों पर एकमुश्त अग्रिम स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान की सुविधा दी जायेगी।
- भारतीय स्टाम्प अधिनियम में Securities Instruments पर स्टाम्प ड्यूटी की एक समान दर व राज्यों में वितरण की व्यवस्था के समान प्रावधान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम में भी किए जायेंगे।
- दस्तावेज की वास्तविक श्रेणी छिपाकर स्टाम्प ड्यूटी की अपवंचना रोकने के लिए कलक्टर (मुद्रांक) को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की जायेंगी।

वाणिज्यिक कर विभाग:

- GST ऑडिट प्राधिकरण एवं बिजनेस इंटेलीजेंस यूनिट का गठन किया जायेगा। करदाताओं के हित में वाणिज्यिक कर विभाग का समग्र पुनर्गठन किया जायेगा।
- प्रशासनिक ढांचे में एकरूपता लाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के पदनाम भारत सरकार के अधिकारियों के समकक्ष किये जायेगे।

- जीएसटी के अंतर्गत माल परिवहन में सुगमता लाने एवं आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु राज्य के मुख्य मार्गों पर Radio Frequency Identification Device (RFID) व Automatic Number Plate Recognition (ANPR) नेटवर्क पर आधारित पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जायेगा।

उपनिवेशन विभाग:

- उपनिवेशन क्षेत्रों के सभी श्रेणियों के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के पेटे दिनांक
- 31 दिसम्बर, 2020 तक, इस तिथि तक की समस्त बकाया किश्तें जमा कराये जाने पर:
    - (i) ब्याज में 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी एवं
    - (ii) बाकी बची हुई किश्तें एकमुश्त जमा कराये जाने पर उपर्युक्त ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

नगरीय विकास, आवासन व राजस्व विभाग:

- स्टेडियम, खेल मैदान एवं क्रीडा संकुलों के निर्माण में निजी संस्थाओं के निवेश को बढ़ावा देने के लिये कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन एवं नियमन हेतु निर्धारित प्रीमियम दरों, भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी।

परिवहन विभाग:

- उप-नगरीय मार्गों की सभी तीन दूरी आधारित श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 50 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह की कमी।
- कॉन्ट्रेक्ट कैरिज बसों की बैठक क्षमता आधारित दो श्रेणियों में मोटर वाहन कर की दर में 100 रूपये प्रति सीट प्रतिमाह की कमी।
- दो नगरपालिकाओं के मध्य स्थित मार्ग जिसकी दूरी 10 किमी. से अधिक नहीं हो पर संचालित वाहनों के मोटर वाहन कर की दर में 100 रूपये प्रतिसीट प्रतिमाह तक सीमित रखा जाना।
- औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ संविदा यान के रूप में संचालित बैठक क्षमता 23 से 32 तक के वाहनों पर आरोपित मोटर वाहन कर में रूपये 14,000/- के स्थान पर 10,000/रूपये रखा जाना।
- Construction Equipment Vehicle एवं Vehicle Fitted with Equipment पर देय एकबारीय कर में समानीकरण करते हुये कर की दर को चैसिस के रूप में क्रय करने पर 8.5 प्रतिशत के स्थान पर 10

प्रतिशत एवं पूर्णतया निर्मित बॉडी के रूप में क्रय करने पर 7 प्रतिशत के स्थान पर 8 प्रतिशत किया जाना ।

- निजी श्रेणी में पंजीकृत वाहनों के व्यावसायिक उपयोग किये जाने पर समान प्रकार के व्यावसायिक वाहन पर देय एकबारीय कर की राशि को 10 प्रतिशत को बढाकर 25 प्रतिशत किया जाना।

खान एवं पैट्रोलियम विभागः

- 'राज्य खनिज अन्वेषण न्यास' का गठन किया जायेगा |
- उत्खनित खनिज एवं रॉयल्टी की गणना हेतु IT व ड्रोन आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जायेगा। उपरोक्त कर प्रस्तावों में कोई भी नया कर नहीं लगाया जा रहा है तथा कर प्रस्तावों से लगभग 130 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई है।